Kamal.Sandesh
kamalsandesh.org
KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-16
16-31 अगस्त, 2025 (पाक्षिक)
₹20

'22 मिनट में हमने 22 अप्रैल का बदला लिया'

'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखी भारत की ताकत'

संसद भवन (नई दिल्ली) में 05 अगस्त, 2025 को एनडीए संसदीय दल की बैठक में 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'ऑपरेशन महादेव' की सफलता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करते एनडीए सांसदगण

7, लोक कल्याण मार्ग (नई दिल्ली) पर 09 अगस्त, 2025 को बच्चों के साथ रक्षा बंधन का त्योहार मनाते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 05 अगस्त, 2025 को फिलीपींस के राष्ट्रपति महामहिम फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर से मुलाकात करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 24 जुलाई, 2025 को 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति–2025' का अनावरण करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

सीतामढ़ी (बिहार) में 08 अगस्त, 2025 को पुनौरा धाम स्थित मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

पटना (बिहार) में 02 अगस्त, 2025 को 'समर्थ बिहार एवं सशक्त भारत' कार्यक्रम को संबोधित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **'ऑपरेशन सिंदूर' एवं 'ऑपरेशन महादेव' की सफलता पर एनडीए सांसदों ने किया प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन**
एन.डी.ए. संसदीय दल की बैठक 05 अगस्त, 2025 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद भवन परिसर में आयोजित की गई...

08 'ऑपरेशन सिंदूर' ने आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को उजागर किया: नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए विजय भावना...

13 22 मिनट में हमने 22 अप्रैल का बदला लिया: जगत प्रकाश नड्डा
राज्यसभा में 30 जुलाई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं...

15 ऑपरेशन सिंदूर का समग्र राजनीतिक-सैन्य उद्देश्य पाकिस्तान को उसके छद्म युद्ध के लिए दंडित करना था: राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 28 जुलाई को लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का...

17 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से आतंकी शिविरों एवं उनके आकाओं का सफाया किया गया: अमित शाह
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले के जबाव...

लेख

विरासत का हस्तांतरण: मोदी जी ने वाजपेयी जी के 'विकसित भारत' के स्वप्न को कैसे साकार किया / **डॉ. के. लक्ष्मण** 19
एनईपी के पांच वर्ष: विकसित भारत की नींव / **धर्मेंद्र प्रधान** 26
स्वदेशी के मंत्र से 'आत्मनिर्भर' होगा भारत / **शिवप्रकाश** 29

मन की बात

यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है: नरेन्द्र मोदी 32

अन्य

पिछले 6 वित्तीय वर्षों में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए 22
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' के लिए कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को दी स्वीकृति 22
ई-श्रम पोर्टल पर 30.95 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत 22
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन 23
प्रधानमंत्री ने वाराणसी से 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान की 20वीं किस्त जारी की 24
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नई दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति से मुलाकात की 28
केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के पुनौरा धाम में माता सीता की जन्मस्थली के समग्र विकास के लिए भूमि पूजन किया 31
अमित शाह जी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बने 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

हमारी सरकार भारतवर्ष के नव-निर्माण में जुटी है, जिसमें पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक देश का कोई भी हिस्सा विकास की धारा से अछूता नहीं है।

(06 अगस्त, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

1947 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उरी आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और तीन दिनों के भीतर, सर्जिकल स्ट्राइक की गईं— सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की राजनीतिक इच्छाशक्ति है।

(30 जुलाई, 2025)

अमित शाह

कांग्रेस के समय में सेना के पास बंदूक, कारतूस तो दूर, नमक, माचिस भी नहीं होती थी...आज हमारी सेना आधे घंटे में पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस को मलबे में बदल देती है।

(30 जुलाई, 2025)

राजनाथ सिंह

बिहार में कानून व्यवस्था सुधरी, सड़कें बनीं, शिक्षा-स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिली और सबसे अहम यहां के लोगों का भरोसा लौटा। आज बिहार विकास की राह पर है और यह संभव हुआ है एनडीए के प्रयासों से।

(02 अगस्त, 2025)

बी.एल. संतोष

'स्थिरता' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की एक बड़ी संपत्ति है। 11 वर्षों से उनके नेतृत्व में सबसे लंबे समय तक पदभार पर रहने वाले गृह मंत्री श्री अमित शाह, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री एवं शिक्षा मंत्री है, जो 'विकसित भारत' को एक मजबूत आकार दे रहे हैं।

(5 अगस्त, 2025)

नितिन गडकरी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र जी की परीक्षा-पे-चर्चा 2025 ने एक महीने में सबसे ज़्यादा पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। यह परिवर्तनकारी मंच छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा के तनाव और सीखने के बारे में खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। इसने भारत में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को नई परिभाषा दी है। इस दूरदर्शी पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक आभार, जो देश भर के युवा मस्तिष्कों का सहानुभूति एवं आत्मविश्वास के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं।

(5 अगस्त, 2025)

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

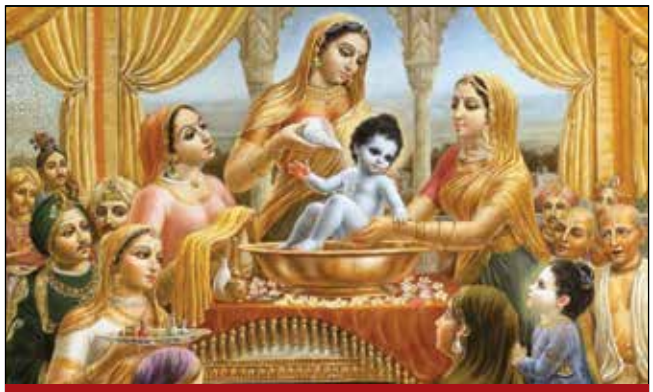

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

संसद में 'विजयोत्सव'

संसद में पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा हुई। पूरा देश पुनः एक बार भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, पराक्रम एवं दृढ़ संकल्प का उत्सव मनाते हुए एकजुट हुआ। यह संसद में सशस्त्र बलों की उन क्षमताओं का 'विजयोत्सव' था जिनके अंतर्गत 7 मई, 2022 को पाकिस्तान एवं पाक-अधिकृत कश्मीर में जवाबी कार्रवाई कर लगभग 100 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहां स्थित आतंकी अवसंरचनाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। हमारी यह कार्रवाई सीमित थी, लेकिन पाकिस्तान ने पुनः हमले का दुस्साहस किया जिसके उत्तर में भारत ने पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करते हुए इसके अनेक हवाई अड्डों को मटियामेट कर दिया। पाकिस्तान युद्धविराम की गुहार लगाने पर मजबूर हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ निश्चयी नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' को बार-बार स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। किसी भी आतंकी हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा और पाकिस्तान के साथ वार्ता और उसका आतंकवाद को समर्थन एक साथ स्वीकारा नहीं जाएगा। ध्यान देने योग्य है कि भारत की मजबूत आतंक प्रतिरोधी नीति न केवल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करती है, बल्कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने झुकती भी नहीं है। पूरे विश्व में भारत की आतंकवाद के विरुद्ध राजनयिक सफलता तथा टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करवाने में प्राप्त कामयाबी इस बात का प्रमाण है।

संसद ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की भारी सफलता को 'विजयोत्सव' के रूप में मनाया, वहीं कांग्रेसनीत विपक्ष की पाकिस्तानी प्रोपगैंडा के सुर में सुर मिलाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति करने के लिए कड़ी भर्त्सना भी हुई है

भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर सफलता का प्रमाण इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के जुलाई, 2025 में प्रकाशित वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक अपडेट से मिलता है। इस रिपोर्ट में भारत को विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2025 तथा 2026 में भारत की विकास दर 6.4 प्रतिशत रहेगी। जहां अप्रैल में 2025 के लिए 6.2 प्रतिशत तथा 2026 के लिए 6.3 प्रतिशत का अनुमान लगाया था, जुलाई में इन दोनों वर्षों के अनुमान सुधार कर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है। कैलेंडर वर्ष के अनुसार आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर को 6.7 प्रतिशत तथा 2026 के लिए 6.4 प्रतिशत रखा है। भारत की यह विकास दर विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कहीं आगे है। चीन के लिए 2025 में 4.8 प्रतिशत तथा 2026 में 4.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान है। वहीं, अमेरिका के लिए 2025 में 1.9 प्रतिशत तथा 2026 में 2.0 प्रतिशत के विकास दर का अनुमान है। यूरोप क्षेत्र के लिए 2025 में 1.6 प्रतिशत तथा 2026 में 1.2 प्रतिशत जबकि जापान के लिए 2025 में 0.7 प्रतिशत तथा 2026 में 0.5 प्रतिशत की भविष्यवाणी की गई है। आईएमएफ ने भारत के विकास का श्रेय लगातार होते आर्थिक सुधारों एवं स्थिर आर्थिक आधारों को दिया है। इसने यह भी रेखांकित किया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था लचीलेपन के कारण वैश्विक आर्थिक विकास को गति दे रही है। विकास दर में सकारात्मक सुधार से विश्व की सर्वाधिक तेज विकास दर वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के भारत के दर्जे पर पुनः मुहर लगी है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तथा जी-20 देशों में सबसे तेज विकास दर के साथ भारत पिछले ग्यारह वर्षों में 30 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से निकालने में सफल रहा है।

जहां संसद ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की भारी सफलता को 'विजयोत्सव' के रूप में मनाया, वहीं कांग्रेसनीत विपक्ष की पाकिस्तानी प्रोपगैंडा के सुर में सुर मिलाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति करने के लिए कड़ी भर्त्सना भी हुई है। कांग्रेसनीत यूपीए के दौर के घुटना-टेक नीति के ठीक विपरीत मोदी सरकार के निर्णायक एवं कड़े कदमों की प्रशंसा आज चारों तरफ हो रही है। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा दिया था, जिसे मोदी सरकार ने रद्द कर दिया। साथ ही, वीजा तथा अटारी-वाघा सीमा से व्यापार पर भी रोक लगा दी। 'अमन की आशा' जैसी सीमा पार पहलों को बंद किया गया तथा सिंधु-जल समझौते को स्थगित किया गया है। सीडीएस की नियुक्ति, संयुक्त अभियानों के लिए सशस्त्र बलों का समायोजन, रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' की पहल, रक्षा बजट में तीन-गुणा से भी अधिक की बढ़ोतरी, घरेलू रक्षा उत्पादों में 250 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा 100 से अधिक देशों में रक्षा निर्यात में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता के मंत्र से युक्त अत्याधुनिक हथियारों एवं उत्पादों से भारत की रक्षा क्षमता कई गुणा अधिक बढ़ चुकी है। वास्तव में देश के पास अनगिनत उपलब्धियों का अंबार है, जो अद्भुत एवं अभूतपूर्व हैं, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' पर संसद में हुए विशेष चर्चा के दौरान देश के समक्ष आया। यह वास्तव में संसद में 'विजयोत्सव' था। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

'ऑपरेशन सिंदूर' एवं 'ऑपरेशन महादेव' की सफलता पर एनडीए सांसदों ने किया प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन

एन.डी.ए. संसदीय दल की बैठक 05 अगस्त, 2025 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद भवन परिसर में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं अन्य एन.डी.ए. सांसद उपस्थित थे। बैठक के दौरान एन.डी.ए. नेताओं ने 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'ऑपरेशन महादेव' की सफलता के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई दी। इन अभियानों की सफलता पर एन.डी.ए. सांसदों द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें सशस्त्र बलों की भूमिका और उनकी अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की गई। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के प्रति भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एन.डी.ए. संसदीय दल के प्रस्ताव में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अद्वितीय नेतृत्व की भी सराहना की गई और कहा गया कि उनके अटल संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और सशक्त कमान ने हर भारतीय के हृदय में एक नई एकता एवं गर्व की भावना भी जाग्रत की है। एन.डी.ए. संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू किए गए रक्षा सुधारों को भी रेखांकित किया गया, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक साबित हुए। प्रस्ताव में कहा गया कि एन.डी.ए. सरकार एक सशक्त, विकसित और शांतिपूर्ण भारत के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। आने वाले समय में ये प्रयास और भी अधिक जोश के साथ जारी रहेंगे

पारित प्रस्ताव

एन.डी.ए. संसदीय दल हमारे सशस्त्र बलों की अतुलनीय वीरता और अटूट प्रतिबद्धता को नमन करता है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के दौरान अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता हमारे राष्ट्र की रक्षा के प्रति उनके अडिग समर्पण को दर्शाती है। हम पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

एन.डी.ए. संसदीय दल इस कठिन समय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय नेतृत्व की सराहना करता है। उनका अटल संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और सशक्त कमान न केवल देश को मजबूत स्थिति में बनाया हुआ है, बल्कि हर भारतीय के हृदय में एक नई एकता और गर्व की भावना भी जाग्रत की है।

22 अप्रैल को पाकिस्तान-पोषित आतंकी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) जो कि लश्कर-ए-तैयबा की शाखा और मुखौटा है। इस संगठन द्वारा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला किया गया। इस अमानवीय और बर्बर हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई। आतंकियों ने लोगों को धर्म के आधार पर अलग करके गोलियों से छलनी करने का कृत्य किया।

इस आतंकी हमले से पूरा देश शोक और आक्रोश से भर उठा था। हर भारतीय की भावना को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी से कहा, "आज बिहार की धरती

से मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि भारत हर आतंकी को, उनके समर्थकों को, पहचान कर, खोजकर, दंडित करेगा। हम उन्हें धरती के आखिरी छोर तक खोजकर मारेंगे। आतंकवाद भारत की आत्मा को नहीं तोड़ सकता। आतंकवाद को माफ नहीं किया जाएगा। न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस संकल्प में एकजुट है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है। मैं उन सभी देशों और उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूं जो इन कठिन समय में भारत के साथ खड़े हैं।"

बिहार की धरती से लिया गया संकल्प अब कार्यरूप में परिणत हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में 6-7 मई 2025 की मध्यरात्रि को भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया। सैन्य पराक्रम और सशक्त नेतृत्व के माध्यम से न्याय सुनिश्चित किया गया, यह पुनः सिद्ध हुआ कि भारत आतंक को न तो भूलता है, न माफ करता है।

ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर सटीक, सीमित, गैर बढ़ावा योग्य और लक्षित कार्रवाई की गई। यह भारत की शांति के प्रति प्रतिबद्धता, आतंक के प्रति पूर्ण असहिष्णुता, तथा आतंकी ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकने की संकल्पबद्धता का प्रतीक रहा। 2014 में एन.डी.ए. सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह नीति स्थापित हो चुकी है। जनता आज भी नहीं भूली है कि 2014 से पहले भारत में आतंकवादी ढांचा किस तरह फैला हुआ था। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, वाराणसी, अहमदाबाद, हैदराबाद और यहां तक कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बम विस्फोट आम बात बन चुकी थी। इस स्थिति में जो बदलाव आया है, उसे देशवासियों ने अत्यंत सराहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्थापित 'नव सामान्य' (New Normal) अब भारत के प्रतिरोध की नीति को परिभाषित करता है। यह नीति तीन स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित हैः

पहला, यदि भारत पर कोई आतंकी हमला होता है, तो उसका उसका उचित जवाब दिया जाएगा। हम हमारी शर्तों पर और पूरी दृढ़ता के साथ जवाब देंगे। जहां से भी आतंक की जड़ें निकलती हैं, हम वहां पर सख्त कार्रवाई करेंगे।

दूसरा, भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में विकसित हो रहे आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमला करेगा।

तीसरा, हम आतंकवाद के सरगनाओं और उसे प्रायोजित करने वाली सरकारों में कोई अंतर नहीं करेंगे, दोनों को समान रूप से उत्तर दिया जाएगा।

ऑपरेशन सिंदूर को विशेष रूप से भारत की नारी शक्ति का अपार समर्थन मिला। इस ऑपरेशन का नाम भी अत्यंत मार्मिक है, क्योंकि हमारी संस्कृति में 'सिंदूर' वह पवित्र प्रतीक है जिसे विवाहित महिलाएं अपने मस्तक पर धारण करती हैं। कायर आतंकियों ने हमारे घरों की स्त्रियों से उनका सिंदूर छीनने का दुस्साहस किया था, लेकिन हमारे सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से उसका बदला लिया और करोड़ों भारतीयों की रक्षा की। इस प्रकार एन.डी.ए. संसदीय दल, भारत की माताओं और बेटियों को न्याय दिलाने वाली इस निर्णायक कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' का अभिनंदन करता है। यह वास्तव में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अडिग राष्ट्रीय इच्छाशक्ति का एक सशक्त उदाहरण है।

एन.डी.ए. संसदीय दल ने उन रक्षा सुधारों की भी सराहना की है जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए और जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। यह स्मरण करना आवश्यक है कि मोदी सरकार ही वह सरकार है जिसने सैन्य सुधारों और स्वदेशीकरण (indigenisation) पर विशेष बल दिया। संयुक्तता और समन्वय (jointness and integration) के प्रति प्रतिबद्धता भी इस ऑपरेशन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। प्रधानमंत्री की 'ड्रोन क्रांति' के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी इस अभियान में कारगर सिद्ध हुई। प्रधानमंत्री ने बार-बार स्पष्ट किया है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं को आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है और वे कब, कहां और कैसे कार्रवाई करें, यह निर्णय वे स्वयं लें। ऑपरेशन सिंदूर उसी दिशा में किया गया सशक्त और निर्णायक कदम था।

ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात् प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि विभिन्न दलों के 59 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 32 देशों का दौरा करे, जिससे भारत का दृष्टिकोण वैश्विक मंचों पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। यह भारत द्वारा अब तक चलाया गया सबसे व्यापक वैश्विक संपर्क अभियान (global outreach) है। इस अभियान के माध्यम से यह रेखांकित किया गया कि भारत स्वयं आतंकवाद का शिकार रहा है और दुनिया के किसी भी कोने में किया गया आतंकी हमला मानवता के विरुद्ध किया गया अपराध है। विपक्षी सांसदों की भागीदारी ने भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और प्रधानमंत्री की कूटनीति को दर्शाती है, जो मानते हैं कि राष्ट्रीय हित के मामलों में हम सभी एक साथ हैं।

अमेरिका द्वारा 'द् रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार था उसे 'विदेशी आतंकी संगठन' (FTO) और 'वैश्विक विशेष रूप से नामित आतंकवादी' (SDGT) घोषित करना, तथा ब्रिक्स (BRICS) द्वारा संयुक्त घोषणा में पहलगाम हमले की निंदा करते हुए 'आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता' और 'दोहरे मानकों के पूर्ण अस्वीकार' की प्रतिज्ञा, पाकिस्तान द्वारा अपनी धरती पर फैलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक जीत को दर्शाता है। ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि आज भारत की वैश्विक मंच पर स्थिति और प्रभाव निरंतर सशक्त हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा है।

पिछले 11 वर्षों से एन.डी.ए. सरकार एक सशक्त, विकसित और शांतिपूर्ण भारत के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। आने वाले समय में ये प्रयास और भी अधिक जोश के साथ जारी रहेंगे। ■

'ऑपरेशन सिंदूर' ने आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को उजागर किया: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 जुलाई को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा के दौरान सदन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए सत्र की शुरुआत में मीडिया जगत के साथ अपनी बातचीत का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने सभी माननीय सांसदों से इस सत्र को भारत की विजय का उत्सव और भारत के गौरव को श्रद्धांजलि बताते हुए इसमें सम्मिलित होने की अपील की थी। श्री मोदी ने आतंकवादी ठिकानों के समूल नाश का उल्लेख करते हुए कहा कि विजयोत्सव सिंदूर लगाकर ली गई पवित्र प्रतिज्ञा की पूर्ति का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय भक्ति और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि है। उन्होंने बल देकर कहा, "विजय उत्सव भारत के सशस्त्र बलों के शौर्य और पराक्रम का प्रमाण है।" श्री मोदी ने आगे कहा कि विजयोत्सव 140 करोड़ भारतीयों की एकता, दृढ़ इच्छाशक्ति और सामूहिक विजय का उत्सव है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए विजय भावना के साथ खड़े होने की पुष्टि करते हुए कहा कि जो लोग भारत के दृष्टिकोण को समझने में विफल रहते हैं, उनके लिए वह एक आईना दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह 140 करोड़ नागरिकों की भावनाओं के साथ अपनी आवाज़ मिलाने आए हैं। श्री मोदी ने बल देकर कहा कि इन सामूहिक भावनाओं की गूंज सदन में सुनाई दे रही है और वह उस गूंजती भावना में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए खड़े हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जनता के अटूट

समर्थन और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे राष्ट्र के ऋणी हैं। उन्होंने नागरिकों के सामूहिक संकल्प को स्वीकार किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में उनकी भूमिका की प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुई उस जघन्य घटना की निंदा की, जहां आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों का धर्म पूछकर उन्हें बेरहमी से गोली मार दी थी। श्री मोदी ने इसे क्रूरता की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत को हिंसा की आग में झोंकने और सांप्रदायिक अशांति भड़काने की एक सोची-समझी साज़िश थी। उन्होंने एकजुटता और दृढ़ता से इस साजिश को विफल करने के लिए भारत की जनता का आभार व्यक्त किया।

श्री मोदी ने याद दिलाया कि 22 अप्रैल के बाद उन्होंने दुनिया के सामने भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी में भी एक सार्वजनिक बयान जारी किया था। उन्होंने आतंकवाद को कुचलने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प की घोषणा की और इस बात पर बल दिया षड्यंत्रकर्ताओं को भी कल्पना से भी अधिक सज़ा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को वे विदेश दौरे पर थे, लेकिन एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाने के लिए तुरंत लौट आए। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान आतंकवाद का निर्णायक जवाब देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। श्री मोदी ने दोहराया कि यह एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।

श्री मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं, शक्ति और साहस पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सेना को समय, स्थान और प्रतिक्रिया के तरीके तय करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा कि उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान इन निर्देशों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था और हो सकता है कि कुछ पहलुओं की मीडिया में भी रिपोर्टिंग हुई हो। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आतंकवादियों को दी गई सज़ा इतनी प्रभावशाली थी कि उनके आकाओं की अब भी नींद उड़ी हुई है।

भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल 22 मिनट में अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त किया

श्री मोदी ने कहा कि वह सदन के माध्यम से भारत की प्रतिक्रिया और उसके सशस्त्र बलों की सफलता को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना को भारत की बड़ी प्रतिक्रिया का अंदेशा था, जिसके कारण उन्होंने परमाणु धमकी जारी की। पहले आयाम को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत ने 6 और 7 मई, 2025

की मध्य रात्रि को अपना ऑपरेशन अंजाम दिया, जिससे पाकिस्तान प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गया। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल 22 मिनट में अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करके 22 अप्रैल के हमले का बदला लिया।

श्री मोदी ने सदन में भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया के दूसरे आयाम को और स्पष्ट करते हुए कहा कि हालांकि भारत ने अतीत में पाकिस्तान के साथ कई युद्ध लड़े हैं, यह पहली बार था जब ऐसी रणनीति अपनाई गई जो पहले अछूते स्थानों तक पहुंची। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निर्णायक रूप से निशाना बनाया गया, जिनमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल थे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत उन क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। उन्होंने बहावलपुर और मुरीदके का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि इन ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया, जिससे यह पुष्टि हुई कि भारत के सशस्त्र बलों ने आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है।

श्री मोदी ने तीसरे आयाम पर बल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की परमाणु धमकियां खोखली साबित हुई हैं और भारत ने दिखा दिया है कि परमाणु ब्लैकमेलिंग को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही भारत कभी उसके सामने झुकेगा।

प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया के चौथे आयाम को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र में अंदर तक सटीक हमले करके अपनी उन्नत तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के हवाई ठिकानों को काफी नुकसान हुआ है, जिनमें से कई गंभीर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि हम अब तकनीक संचालित युद्ध के युग में हैं और ऑपरेशन सिंदूर ने इस क्षेत्र में भारत की महारत सिद्ध कर दी है। इस बात पर बल देते हुए कि अगर भारत ने पिछले दस वर्षों की तैयारी नहीं की होती, तो देश को इस तकनीकी युग में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, श्री मोदी ने पांचवें आयाम को प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी है। उन्होंने भारत में निर्मित ड्रोन और मिसाइलों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला, जिससे पाकिस्तान की हथियार प्रणालियों की कमजोरियां उजागर हुईं।

ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना, सेना और वायु सेना की संयुक्त कार्रवाई

प्रधानमंत्री ने भारत की रक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) की घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना, सेना और वायु सेना की संयुक्त कार्रवाई देखी गई और इन बलों के बीच तालमेल ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला दिया।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में पहले भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनके षड्यंत्रकर्ता बेख़ौफ़ थे और बेख़ौफ़ होकर भविष्य के हमलों की योजना बनाते रहे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अब स्थिति बदल गई है। आज, हर हमले के बाद षड्यंत्रकर्ताओं की नींद उड़ जाती है, यह जानते हुए कि भारत जवाबी हमला करेगा और ख़तरों को सटीकता से ख़त्म कर देगा। श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि भारत ने एक 'न्यू नॉर्मल' स्थापित किया है।

इस बात पर जोर देते हुए कि वैश्विक समुदाय अब भारत के रणनीतिक अभियानों के विशाल पैमाने और पहुंच को देख चुका है, उन्होंने कहा कि सिंदूर से सिंधु तक पूरे पाकिस्तान में हमले किए गए। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया सिद्धांत स्थापित किया हैः भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का उसके षड्यंत्रकर्ताओं और स्वयं पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से निकलने वाले तीन स्पष्ट सिद्धांतों को रेखांकित किया। पहला, भारत आतंकवादी हमलों का अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से और अपने चुने हुए समय पर जवाब देगा। दूसरा, किसी भी तरह का परमाणु ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरा, भारत आतंकवादियों के प्रायोजकों और ऐसे हमलों के पीछे के षड्यंत्रकर्ताओं के बीच कोई भेद नहीं करेगा।

श्री मोदी ने सदन को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कार्रवाई को मिले वैश्विक समर्थन की स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने कहा कि

मुख्य बातें

- विजय उत्सव भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और शक्ति का प्रमाण है
- मैं इस विजय उत्सव की भावना के साथ सदन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना, सेना और वायु सेना के तालमेल ने पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया
- भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी शर्तों पर आतंक का जवाब देगा, परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंक के प्रायोजकों और षड्यंत्रकर्ताओं के साथ समान व्यवहार करेगा
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को व्यापक वैश्विक समर्थन मिला
- ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान के किसी भी लापरवाह कदम का कड़ा जवाब दिया जाएगा
- सीमाओं पर एक मजबूत सेना एक जीवंत और सुरक्षित लोकतंत्र सुनिश्चित करती है
- ऑपरेशन सिंदूर पिछले एक दशक में भारत के सशस्त्र बलों की बढ़ती शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है
- भारत बुद्ध की भूमि है, युद्ध की नहीं, हम समृद्धि और सद्भाव के लिए प्रयासरत हैं, यह जानते हुए कि स्थायी शांति शक्ति से आती है

दुनिया के किसी भी देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने पर आपत्ति नहीं जताई। प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से केवल तीन देशों ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान जारी किए। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया भर के देशों से व्यापक समर्थन मिला, जिसमें क्वाड और ब्रिक्स जैसे रणनीतिक समूह और फ्रांस, रूस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ मज़बूती से खड़ा है।

देश के सैनिकों के पराक्रम को विपक्ष का समर्थन नहीं मिला

इस बात पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कि भारत को वैश्विक समुदाय से समर्थन तो मिला, लेकिन देश के सैनिकों के पराक्रम को विपक्ष का समर्थन नहीं मिला, श्री मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के कुछ ही दिनों बाद कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया और उस पर विफलता का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मज़ाक और पहलगाम नरसंहार के बाद भी राजनीतिक अवसरवाद में उनकी लिप्तता, राष्ट्रीय शोक के प्रति उपेक्षा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान न केवल तुच्छ हैं, बल्कि भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल भी गिराने वाले हैं। श्री मोदी ने बल देकर कहा कि कुछ विपक्षी नेताओं को न तो भारत की ताकत पर और न ही उसके सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर विश्वास है और वे ऑपरेशन सिंदूर पर संदेह व्यक्त करते रहते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सुर्खियों के पीछे भागने से राजनीतिक हित तो सध सकते हैं, लेकिन इससे लोगों का विश्वास या सम्मान नहीं मिलेगा।

ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत ने एक बार फिर स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य के साथ काम किया— आतंक के केंद्र और पहलगाम घटना के हमलावरों के पीछे के बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जिसमें उनके योजना आधार, प्रशिक्षण केंद्र, धन स्रोत, ट्रैकिंग और तकनीकी सहायता और हथियारों की आपूर्ति शृंखलाएं शामिल थीं

पिछले कुछ वर्षों में भारत के लक्षित सैन्य अभियानों को याद करते हुए रणनीतिक स्पष्टता और कार्यान्वयन पर ज़ोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत ने दुश्मन के इलाके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का एक स्पष्ट लक्ष्य रखा था, जिसे सूर्योदय से पहले रात भर में पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि बालाकोट हवाई हमलों में भारत ने आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाया और सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत ने एक बार फिर स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य के साथ काम किया— आतंक के केंद्र और पहलगाम घटना के हमलावरों के पीछे के बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जिसमें उनके योजना आधार, प्रशिक्षण केंद्र, धन स्रोत, ट्रैकिंग और तकनीकी सहायता और हथियारों की आपूर्ति शृंखलाएं शामिल थीं। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत ने इन आतंकवादियों के केंद्र पर सटीक हमला किया और उनके अभियानों की जड़ों को ध्वस्त कर दिया।"

श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा, "एक बार फिर भारतीय सेना ने अपने लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल किया और देश की ताकत का परिचय दिया।"

प्रधानमंत्री ने सदन में आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की निर्णायक कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तानी नागरिकों ने आश्चर्य व्यक्त किया, जिनकी प्रतिक्रियाएं टेलीविजन पर व्यापक रूप से दिखाई गईं। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान इस प्रतिक्रिया से इतना अभिभूत था कि उसके सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) ने सीधे भारत को फोन किया और आक्रमण रोकने की विनती की, यह स्वीकार करते हुए कि वे और अधिक हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते।

हम गोलियों का जवाब गोलों से देंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी वैश्विक नेता ने भारत के अभियानों पर आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने खुलासा किया कि 9 मई की रात, जब वे भारतीय रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक में थे, तब अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री को फोन पर जवाब देने पर, उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दियाः "अगर पाकिस्तान की यही मंशा है, तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।" उन्होंने दृढ़ता से कहा कि भारत और भी ज़ोरदार तरीके से जवाबी कार्रवाई करेगा। श्री मोदी ने कहा, "हम गोलियों का जवाब गोलों से देंगे।"

श्री मोदी ने भारत की सैन्य उपलब्धियों पर सवाल उठाने और उन्हें कमतर आंकने की लगातार कोशिशों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की सफल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विपक्षी नेताओं ने सशस्त्र बलों से सबूत मांगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही जनता की भावना सेना के पक्ष में हुई, विपक्षी नेताओं ने अपना रुख बदलते हुए दावा किया कि उन्होंने भी ऐसे हमले किए थे तथा अलग-अलग संख्या में सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे, जिनकी संख्या तीन से लेकर पंद्रह तक थी।

प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि बालाकोट हवाई हमलों के बाद विपक्ष इस ऑपरेशन को सीधे चुनौती नहीं दे सका, बल्कि इसके बजाय फ़ोटोग्राफ़िक सबूत मांगने लगा। उन्होंने कहा कि वे बार-बार पूछ रहे थे कि हमला कहां हुआ, क्या नष्ट हुआ, कितने लोग मारे गए। उन्होंने बताया कि ये सवाल पाकिस्तान की अपनी बयानबाज़ी से मिलते-जुलते थे।

विपक्ष पाकिस्तान को क्लीन चिट देता दिख रहा है

श्री मोदी ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि विपक्ष पाकिस्तान को क्लीन चिट देता दिख रहा है। उन्होंने पहलगाम के आतंकवादियों के पाकिस्तानी नागरिक होने के सबूत की विपक्ष द्वारा उठाई गई मांग पर सवाल उठाया और कहा कि यही मांग खुद पाकिस्तान भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में भी ऐसी ही आदतें और दुस्साहस मौजूद हैं, जो बाहरी बयानों की प्रतिध्वनि हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज, जनता के सामने सबूतों और तथ्यों की कोई कमी नहीं है, फिर भी कुछ लोग संदेह पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसे स्पष्ट सबूत उपलब्ध न होते तो ये लोग कैसी प्रतिक्रिया देते, जिसका अर्थ है कि उनकी प्रतिक्रियाएं और भी भ्रामक या गैर-ज़िम्मेदाराना होतीं।

श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा विपक्ष ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कामकाज से पूरी तरह वाकिफ है। प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस अनुभव के बावजूद उन्होंने लगातार आधिकारिक स्पष्टीकरण स्वीकार करने से इनकार कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि चाहे विदेश मंत्रालय का बयान हो, विदेश मंत्री के बार-बार दिए गए जवाब हों, या गृह और रक्षा मंत्रियों के स्पष्टीकरण हों, विपक्ष उन पर भरोसा करने से इनकार करता है। उन्होंने सवाल किया कि दशकों तक शासन करने वाली पार्टी देश की संस्थाओं में इतना अविश्वास कैसे दिखा सकती है। श्री मोदी ने बल देकर कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष अब पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल के अनुसार काम कर रहा है और उसका रुख भी उसी के अनुसार बदल रहा है।

श्री मोदी ने विपक्ष के उन वरिष्ठ नेताओं की आलोचना की जो लिखित बयान तैयार करते हैं और युवा सांसदों से अपनी बात मनवाते हैं। उन्होंने ऐसे नेतृत्व की निंदा की क्योंकि उनमें खुद बोलने का साहस नहीं है और उन्होंने 26 लोगों की जान लेने वाले एक क्रूर आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को 'एक तमाशा' बताया। उन्होंने इस बयान को एक भयावह घटना की स्मृति पर तेज़ाब डालने जैसा बताया और इसे एक शर्मनाक कृत्य बताया।

श्री मोदी ने बताया कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने पिछले दिन ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत मार गिराया था। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ऑपरेशन के समय को लेकर पूछे गए सवालों पर हंसी-मज़ाक का दौर चला और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा गया कि क्या यह सावन के महीने के किसी पवित्र सोमवार को निर्धारित था। उन्होंने इस रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए इसे घोर निराशा और हताशा का प्रतीक बताया और कहा कि यह विपक्ष के बिगड़ते रवैये को दर्शाता है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी उपकरणों के लिए भी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहा। उन्होंने बुलेटप्रूफ जैकेट और नाइट विज़न कैमरों की कमी जैसी कमियों का ज़िक्र किया और बताया कि जीप से लेकर बोफोर्स और हेलीकॉप्टर तक, हर रक्षा खरीद में घोटाले जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय सेनाओं को आधुनिक हथियारों के लिए दशकों तक इंतज़ार करना पड़ा

विपक्ष के शासन के दौरान हर रक्षा सौदा निजी लाभ का अवसर था

श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के शासन के दौरान हर रक्षा सौदा निजी लाभ का अवसर था। उन्होंने कहा कि भारत बुनियादी उपकरणों के लिए भी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहा। श्री मोदी ने बुलेटप्रूफ जैकेट और नाइट विज़न कैमरों की कमी जैसी कमियों का ज़िक्र किया और बताया कि जीप से लेकर बोफोर्स और हेलीकॉप्टर तक, हर रक्षा खरीद में घोटाले जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय सेनाओं को आधुनिक हथियारों के लिए दशकों तक इंतज़ार करना पड़ा।

श्री मोदी ने याद दिलाया कि एक दशक पहले भारतीयों ने एक मज़बूत, आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था, जिसके परिणामस्वरूप आज़ादी के बाद पहली बार कई सुरक्षा सुधार लागू किए गए। उन्होंने कहा कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष की नियुक्ति एक बड़ा सुधार था, जिस पर दुनिया भर में लंबे समय से बहस और अभ्यास चल रहा था, लेकिन भारत में इसे कभी लागू नहीं किया गया। उन्होंने तीनों सेनाओं द्वारा इस प्रणाली के पूरे दिल से समर्थन और स्वीकृति की प्रशंसा की।

इस बात पर बल देते हुए कि आज की सबसे बड़ी ताकत संयोजन और एकीकरण में निहित है, श्री मोदी ने कहा कि नौसेना, वायुसेना और थलसेना के एकीकरण से भारत की रक्षा क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है और ऑपरेशन सिंदूर इस परिवर्तन की सफलता को दर्शाता है।

श्री मोदी ने कहा कि अशांति और हड़तालों सहित शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद सरकारी स्वामित्व वाली रक्षा उत्पादन कंपनियों में सुधार लागू किए गए। उन्होंने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने, सुधारों को अपनाने और अत्यधिक उत्पादक करने के लिए कर्मचारियों की प्रशंसा की। उन्होंने आगे बताया कि भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है और आज निजी क्षेत्र उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। श्री मोदी ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में सैकड़ों स्टार्टअप, जिनमें से कई का नेतृत्व टियर-2 और टियर-3 शहरों के 27-30 वर्ष की आयु के युवा पेशेवरों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें युवतियां भी शामिल हैं, नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

पिछले एक दशक में भारत का रक्षा बजट लगभग तीन गुना बढ़ा

रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को केवल एक नारा न मानते हुए

श्री मोदी ने कहा कि बजट में वृद्धि, नीतिगत बदलाव और नई पहल एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ की गईं, जिससे स्वदेशी रक्षा निर्माण में तेज़ी से प्रगति हुई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा बजट लगभग तीन गुना बढ़ गया है। पिछले 11 वर्षों में रक्षा उत्पादन में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और रक्षा निर्यात 30 गुना से भी अधिक बढ़ा है, जो अब लगभग 100 देशों तक पहुंच रहा है।

श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि विपक्ष के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कभी कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रहा और उसने लगातार उससे समझौता किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस क्यों नहीं लिया गया, उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि आख़िर पाकिस्तान को उस पर कब्ज़ा करने की इजाज़त किसने दी।

स्वतंत्रता के बाद के उन फैसलों की कड़ी आलोचना करते हुए, जो देश पर बोझ बने हुए हैं, श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि गलत फ़ैसलों के कारण अक्साई चिन में 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय ज़मीन का नुकसान हुआ, जिसे ग़लती से बंजर भूमि बता दिया गया। उन्होंने कहा कि 1962 और 1963 के बीच तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ, उरी, नीलम घाटी और किशनगंगा सहित प्रमुख क्षेत्रों को सौंपने का प्रस्ताव रखा था।

श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि आत्मसमर्पण का प्रस्ताव 'शांति रेखा' की आड़ में रखा गया था। उन्होंने 1966 में कच्छ के रण पर मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए विपक्ष की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप विवादित छड़-बेट क्षेत्र सहित लगभग 800 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान को सौंप दी गई। उन्होंने याद दिलाया कि हालांकि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने हाजीपीर दर्रे पर पुनः कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन तत्कालीन सत्तारूढ़ दल ने उसे वापस कर दिया, जिससे देश की रणनीतिक जीत कमज़ोर हो गई।

श्री मोदी ने बल देकर कहा कि 1971 के युद्ध के दौरान भारत ने हज़ारों वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था और 93,000 युद्धबंदी बनाए थे। उन्होंने कहा कि अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (पीओके) को वापस पाने का मौका गंवा दिया गया। यहां तक कि सीमा के पास स्थित करतारपुर साहिब भी सुरक्षित नहीं हो सका। उन्होंने 1974 में कच्चातीवु द्वीप को श्रीलंका को दान करने के फ़ैसले पर खेद व्यक्त किया और इस हस्तांतरण के कारण तमिलनाडु के मछुआरों को हो रही कठिनाइयों का ज़िक्र किया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि विपक्ष दशकों से सियाचिन से भारतीय सेना को हटाने की मंशा रखता रहा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो रहा है।

श्री मोदी ने सदन को याद दिलाया कि 26/11 के भयावह मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन सरकार ने कथित तौर पर विदेशी दबाव में त्रासदी के कुछ ही हफ़्तों बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि 26/11 की भयावहता के बावजूद तत्कालीन सरकार ने एक भी पाकिस्तानी राजनयिक को निष्कासित नहीं किया और न ही एक भी वीज़ा रद्द किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमले बेरोकटोक जारी रहे, फिर भी तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान को 'सर्वाधिक तरजीही वाले राष्ट्र' का दर्जा मिलता रहा, जिसे कभी रद्द नहीं किया गया।

सिंधु जल संधि स्थगित

भारत के जल अधिकारों और विकास, विशेष रूप से सिंधु जल संधि के अंतर्गत समझौता करने वाले ऐतिहासिक कूटनीतिक फैसलों की निंदा करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत से निकलने वाली नदियों का 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को आवंटित करने पर सहमत हुए थे, जबकि भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए केवल 20 प्रतिशत ही बचा था। उन्होंने इस व्यवस्था के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाते हुए इसे बुद्धिमत्ता, कूटनीति और राष्ट्रीय हित की विफलता बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने नहरें बनाने के लिए पाकिस्तान को करोड़ों रुपये भी दिए, जिससे भारत के हितों को और नुकसान पहुंचा। श्री मोदी ने बताया कि सरकार ने अब राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे।"

श्री मोदी ने एकजुटता की भावना का आह्वान करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद भले ही बने रहें, लेकिन राष्ट्रहित में उद्देश्य की एकता बनी रहनी चाहिए।

उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडलों की प्रशंसा की, जिन्होंने दृढ़ विश्वास और स्पष्टता के साथ विश्व स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी वकालत उस 'सिंदूर भावना' की प्रतिध्वनि थी जो अब भारत की सीमाओं के भीतर और बाहर, दोनों जगह, स्थिति का मार्गदर्शन करती है।

भारत के मुखर वैश्विक संदेश का कथित रूप से विरोध करने वाले कुछ विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने सदन में राष्ट्र के पक्ष में बोलने वालों को चुप कराने के प्रयासों पर खेद व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जो पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी है, जब तक सीमा पार आतंकवाद नहीं रुकता, भारत अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा।

श्री मोदी ने भारत के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखने के दृढ़ संकल्प के साथ अपने भाषण का समापन किया और लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाले सार्थक विचार-विमर्श के लिए सदन के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। ■

राज्यसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा

22 मिनट में हमने 22 अप्रैल का बदला लिया: जगत प्रकाश नड्डा

राज्यसभा में 30 जुलाई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जब यह सदन 21 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ था, मैंने उस समय विपक्ष के नेता से कहा था कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हम पहलगाम हमले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और इसके हर विवरण में जाने के लिए तैयार हैं। व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में यह तय हुआ था और हम यहां 16 घंटे की चर्चा कर रहे हैं। पहलगाम की घटना अत्यंत हृदय विदारक, दुखद और मानवता को झकझोर देने वाली है। इस निंदनीय कृत्य के लिए कितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। यह निंदनीय है और हम सभी सर्वसम्मति से इस घटना की निंदा करते हैं। यहां प्रस्तुत है श्री नड्डा के संबोधन के प्रमुख अंश:

आपने मुझे ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इस गंभीर विषय पर चर्चा करने का मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं कि इस घटना में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक ने अपनी जान गंवाई। यह घटना इतनी कठोर थी कि यह किसी के लिए भी असहनीय है और इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है।

जो निश्चित है, वह है हमारी बहादुर सेनाओं ने, हमारी पुलिस ने, हमारी सेना ने इस पूरी घटना में जो भूमिका निभाई, देश सम्मान के साथ उनके सामने नतमस्तक है और उनके प्रति सम्मान के साथ खड़ा है। लेकिन इस सदन के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि राजनीतिक नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व सेनाओं को आदेश देता है। इसलिए एक जिम्मेदार सरकार, एक उत्तरदायी सरकार, एक संवेदनशील सरकार, एक सक्रिय सरकार और समय की आवश्यकता के अनुसार जवाब देने वाली एक सरकार के बीच अंतर होता है।

एक और तरह की सरकार भी होती है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व का प्रश्न उठता है, जिसे हम एक निष्क्रिय सरकार, एक शिथिल रवैये वाली सरकार, एक गैर-प्रतिक्रियाशील और अनुत्तरदायी सरकार कहते हैं। इस अंतर को समझने के लिए यदि हम केवल पहलगाम की घटना को अकेले देखें, तो हम देश और इस कथा के साथ अन्याय कर सकते हैं। हमें इसे समग्रता में देखने की आवश्यकता है। मैं 1947 से शुरू नहीं करूंगा, मैं सिर्फ़ एक चरण ले रहा हूं।

- 2005 में जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस में हरकत-उल-जिहाद ने एक बम विस्फोट किया। चौदह लोग मारे गए और 62 घायल हुए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे रिकॉर्ड पर रहने दें। जो लोग आज हमसे पूछ रहे हैं कि पहलगाम का क्या हुआ, उन्हें पहले अपने दिल में झांककर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया।
- 29 अक्टूबर, 2005 को दिल्ली में सरोजिनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी में दिल्ली सीरियल बम धमाके हुए। इसे लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया। कितने लोग मारे गए? 67 लोग मारे गए और 200 घायल हुए। यह बम विस्फोट दिवाली से ठीक पहले हुआ था। आप उस समय की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं और सरकार की असंवेदनशीलता को समझ सकते हैं। कोई कार्रवाई नहीं की गई।

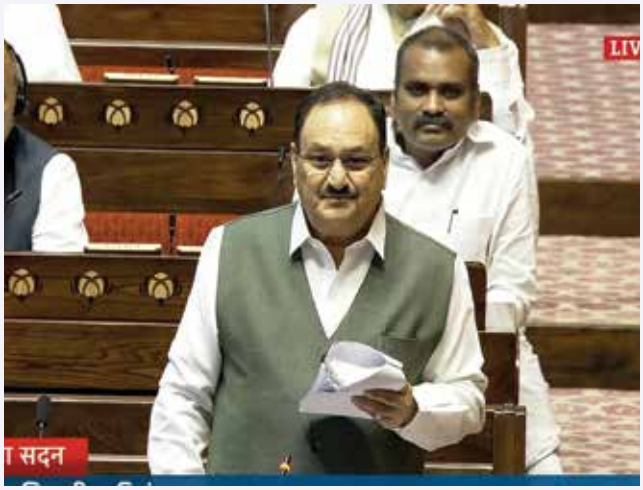

- 7 मार्च, 2006 को वाराणसी में संकट मोचन मंदिर, वाराणसी छावनी और रेलवे स्टेशन पर वाराणसी बम विस्फोट हुआ, जिस पर हरकत-उल-जिहाद ने हमला किया। मरने वालों की संख्या 28 थी, जिसमें 100 घायल थे। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- 11 जुलाई, 2006 को मुंबई ट्रेन बम विस्फोट किया गया। इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा ने इसे अंजाम देने के लिए हाथ मिलाया। कितने लोग मारे गए? 209 लोग मारे गए और 700 घायल हुए। इसके बाद एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी तंत्र की स्थापना की गई, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आतंकवाद की राज्य नीति कैसे तैयार की जाएगी। यह तंत्र दो महीने बाद मिला

और दूसरी बैठक सात महीने बाद हुई। कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- 13 मई, 2008 को जयपुर में कई स्थानों पर जयपुर बम विस्फोट हुआ, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन शामिल था। 71 लोग मारे गए और 185 घायल हुए। इसके बाद क्या हुआ? 2008 में भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर-विशिष्ट (specific) विश्वास-निर्माण उपायों के एक समूह पर सहमति व्यक्त की। हम विश्वास-निर्माण उपायों का पीछा कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान हम पर गोलियां चलाता रहा और हम उन्हें बिरयानी खिलाते रहे।
- 26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद में कई स्थानों पर अहमदाबाद सीरियल बम धमाके हुए, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन शामिल था। इन हमलों में 56 लोग मारे गए। इन हमलों में मारे गए लोगों की संख्या देखें— कभी 70, कभी 56, कभी 100, कभी 209।
- 13 सितंबर, 2008 को दिल्ली में कनॉट प्लेस, गफ्फार मार्केट और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में दिल्ली सीरियल बम विस्फोट हुआ, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन शामिल था। 30 लोग मारे गए जबकि 133 घायल हुए। इसके बाद आपने क्या किया? यह घटना 2008 की थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सितंबर, 2008 में मुज़फ़्फ़राबाद में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और 21 अक्टूबर, 2008 को पुंछ-रावलकोट सड़क को भी व्यापार के लिए खोल दिया गया।
- लश्कर-ए-तैयबा ने ताज महल होटल, ओबेरॉय-ट्राइडेंट, चबाड हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में मुंबई आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली। 166 लोग मारे गए, जबकि 300 घायल हुए। हमारी सरकार ने क्या किया? उन्होंने एक डोजियर भेजा!

आतंकवादी घटनाओं में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी आई

अब दूसरा चरण देखें— 2014 से अमावस्या ढलना शुरू हो गई। एकादशी आई, द्वादशी आई और इस तरह हम पूर्णिमा की ओर बढ़े। 2014 में पूरे देश में- और मैं इसे रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं - गृह मंत्री आएंगे और अपने बयान में सभी विवरण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में आतंकवादी हमले बंद हो गए हैं। हमें इसे समझने की आवश्यकता है।

अब देखिए 2014 से 2025 तक आज तक जम्मू-कश्मीर को छोड़कर आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई है। 2004 से 2014 तक आतंकवादी घटनाओं की संख्या 7,217 थी। 2015 से 2025 तक संख्या 2,115 तक गिर गई— 80 प्रतिशत से अधिक की कमी। हम हिसाब दे रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं।

2004 और 2014 के बीच 1,770 नागरिक मौतें हुईं। यह संख्या 2015 और 2025 के बीच सिर्फ़ 357 तक गिर गई, जो 70 प्रतिशत की कमी है। सुरक्षा कर्मियों की मौतें 2004 से 2014 तक 1,060 थीं। यह 2015 से 2025 तक 542 तक कम हो गई— 49 प्रतिशत की कमी। दूसरी ओर इस अवधि के दौरान आतंकवादी मौतों की संख्या में 123 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अब हम सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करना चाहते हैं। 18 सितंबर, 2016 को उरी में हमारे ब्रिगेड मुख्यालय में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर आए और उन्होंने 19 सैनिकों को मार डाला। मैं इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेना तब भी थी और अब भी है। वही सेनाएं तब भी थीं और अब भी हैं। राजनीतिक नेतृत्व अलग था।

जब जैश-ए-मोहम्मद ने आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली तो बालाकोट हवाई हमला हुआ। एक वाहन में भरे विस्फोटकों ने हमारे 40 सीआरपीएफ कर्मियों को मार डाला। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यहां पालम हवाई अड्डे पर सभी को श्रद्धांजलि दी और फिर एक बयान दिया। बयान क्या था? "पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।" राजनीतिक इच्छाशक्ति देखें।

11 दिनों के भीतर बालाकोट का जवाब दिया गया था। 70 किलोमीटर अंदर तक घुसकर 5,000 किलोग्राम गोला-बारूद गिराया गया था और हमने वहां उनके सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया।

हमने आतंक के बुनियादी ढांचे पर हमला किया

पहलगाम हमला आपके सामने है। हम सभी जानते हैं कि 13 दिनों के भीतर जवाब दिया गया था— ऑपरेशन सिंदूर। हमने आतंक के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। हम सटीकता और परिशुद्धता के साथ पाकिस्तान के हवाई ठिकानों के 300 किलोमीटर अंदर गए। किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वहां मौजूद कोई भी आतंकवादी जीवित नहीं बचा।

इसी तरह सुरक्षा बलों ने आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए नौ मिसाइलों का उपयोग किया। उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। बहावलपुर, मरकज़-ए-तैयबा, नारोवाल, सियालकोट, बरनाला, कोटली, मुज़फ़्फ़राबाद- इन सभी स्थानों पर ठिकानों को नष्ट कर दिया गया।

22 मिनट में हमने 22 अप्रैल का बदला लिया। हमें इसे भी समझने की आवश्यकता है। इतिहास में कभी नहीं- मैं इसे रिकॉर्ड पर कह रहा हूं- किसी भी सरकार ने पाकिस्तान को उस तरह से जवाब नहीं दिया है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 22 मिनट के भीतर दिया।

अंत में सिर्फ़ एक बात कहूंगा। यह देश का सवाल है। विपक्ष को भी इसमें खुद को शामिल करना चाहिए और इसे खुशी के साथ करना चाहिए। अगर कम हंसी है तो उन्हें मुझसे उधार लेना चाहिए। लेकिन हंसी और खुशी के साथ हमें एक आवाज में इसका स्वागत करना चाहिए। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सक्षम, मजबूत और सुरक्षित है। हम आगे बढ़ने और एक छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। ■

लोकसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा

ऑपरेशन सिंदूर का समग्र राजनीतिक-सैन्य उद्देश्य पाकिस्तान को उसके छद्म युद्ध के लिए दंडित करना था: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 28 जुलाई को लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य सीमा पार करना या शत्रु क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान द्वारा वर्षों से पोषित आतंकी ढांचे को नष्ट करना और सीमा पार से किये गये हमलों में अपने प्रियजनों को खोने वाले निर्दोष परिवारों को न्याय दिलाना था। श्री सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अचानक आवेश से भरा पागलपन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति और पुरानी कुंठा बताया और इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का समग्र राजनीतिक-सैन्य उद्देश्य आतंकवाद के छद्म युद्ध लड़ने वाले पाकिस्तान को दंडित करना था

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता, बल्कि अपने राष्ट्रीय संकल्प, नैतिक बल और राजनीतिक कौशल का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत किसी भी आतंकवादी हमले का निर्णायक और स्पष्ट जवाब देगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को पनाह और समर्थन देने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेलिंग या अन्य दबावों के आगे झुकने वाला नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को अमानवीयता का सबसे घिनौना उदाहरण बताया, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर मार डाला गया। यह भारत की सहनशीलता की परीक्षा थी। उन्होंने कहा कि हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री

नरेन्द्र मोदी ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की और सशस्त्र बलों को विवेक, रणनीतिक समझ और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का ध्यान रखते हुए निर्णायक कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर आरंभ किया, जो सिर्फ़ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, अस्मिता और देश के लोगों के प्रति सरकार के दायित्व और आतंकवाद के विरुद्ध उसकी प्रभावी नीति का निर्णायक प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल परिपक्वता दिखाई, बल्कि वैसी रणनीतिक बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की, जिसकी भारत जैसी ज़िम्मेदार शक्ति से अपेक्षा की जाती है।

100 से अधिक आतंकवादी मारे गए

रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने हर पहलू का गहराई से अध्ययन के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि कई विकल्प मौजूद थे, लेकिन हमने वह विकल्प चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों का अधिकतम नुकसान हो, पर आम पाकिस्तानी नागरिकों को कोई क्षति न पहुंचे। रक्षा मंत्री ने कहा कि अनुमान के अनुसार हमारे बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ढांचों पर किए गए सुनियोजित हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक, आका और सहयोगी मारे गए। अधिकतर आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े थे, जिन्हें पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का खुला समर्थन मिला हुआ है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 10 मई, 2025 को पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइलों, ड्रोनों, रॉकेटों और लंबी दूरी के अन्य हथियारों से हमले किये, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का भी व्यापक इस्तेमाल किया और भारतीय वायुसेना के ठिकानों, भारतीय सेना के गोला-बारूद डिपो, हवाई अड्डों और सैन्य छावनियों को निशाना बनाने की कोशिश की। श्री सिंह ने सदन को गर्व से बताया कि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन-रोधी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने पाकिस्तानी हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के हमलों को विफल बनाने में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली एस-400, आकाश मिसाइल और वायु रक्षा तोपों की प्रभावशीलता का भी उल्लेख किया।

रक्षा मंत्री ने सैनिकों की बहादुरी और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि हमारी अचूक सुरक्षा प्रणाली ने दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर दिया, जिससे पाकिस्तान किसी भी भारतीय लक्ष्य को नहीं भेद

सका और हमारे किसी महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा।

भारत का जवाबी हमला— तेज़, संतुलित और सटीक

रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई को साहसिक, दृढ़ और प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के हवाई ठिकानों, कमान और नियंत्रण केंद्रों, सैन्य ढांचों और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया और सफलतापूर्वक मिशन पूरा किया। हमारा जवाबी हमला तेज़, संतुलित और सटीक रहा।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल उन्हीं लोगों और ठिकानों पर लक्ष्य साधा, जो आतंकवादियों को लगातार मदद पहुंचाकर भारत पर हमला करने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य युद्ध छेड़ना कभी नहीं था, बल्कि अपनी शक्ति दिखाकर दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर करना था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा।

रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि 10 मई की सुबह, जब भारतीय वायु सेना ने कई पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भारी हमले किए, तो पाकिस्तान ने हार मान ली और युद्ध विराम की पेशकश करने लगा। उन्होंने कहा कि इसे केवल इस शर्त पर माना गया कि भारतीय अभियान केवल स्थगित किया जाएगा और अगर भविष्य में पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना के हमलों, नियंत्रण रेखा पर भारतीय थल सेना की कड़ी जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर से पाकिस्तान आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गया।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 10 मई को पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क कर सैन्य अभियान रोकने का आग्रह किया। इसके बाद 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक बातचीत के बाद अभियान रोकने का फैसला किया गया।

ऑपरेशन सिंदूर: तीनों सेनाओं के तालमेल का एक उत्कृष्ट उदाहरण

रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के तालमेल का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया, जिसमें भारतीय वायु सेना ने आसमान से हमला किया, भारतीय थल सेना ने नियंत्रण रेखा पर डटकर हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया और भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में अपनी मज़बूत तैनाती से रक्षा सुदृढ़ कर दी। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि हम समुद्र से ज़मीन तक, उनके हर बड़े ठिकाने पर हमला करने में सक्षम और इसके लिए तैयार हैं।

ऑपरेशन सिंदूर दबाव में रोके जाने के दावों को खारिज करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने इन्हें निराधार और गलत बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने कार्रवाई तभी रोकी जब सभी राजनीतिक और सैन्य उद्देश्य पूरी तरह से हासिल हो गए।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर अभियानों से शांति सुनिश्चित करने का एक अलग रास्ता अपनाया है और उसका स्पष्ट रुख है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।

पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद के प्रशिक्षण का गढ़

रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद के प्रशिक्षण का गढ़ है और उसने इसे अपनी राजकीय नीति का आधार बना लिया है। श्री सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने मारे गये आतंकवादियों के अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आयोजित किए, जिसमें वहां के सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान सीमा पर तैनात भारतीय सैन्य बल से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता, इसलिए निर्दोष नागरिकों, बच्चों और तीर्थयात्रियों को आतंकी निशाना बनाता है।

श्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई केवल सीमा पर ही नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी लड़ी जा रही है। उन्होंने उन सभी प्रतिनिधिमंडलों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के विरुद्ध भारत की शून्य सहनशीलता की नीति बरतने (ज़ीरो टॉलरेंस नीति) और ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता बताई। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधाराओं और मतभेदों को दरकिनार करते हुए राष्ट्र, सैनिकों और सरकार के साथ एकजुटता दिखाई।

रक्षा मंत्री ने सदन और देश की जनता को आश्वस्त किया कि सरकार, सशस्त्र बल और लोकतांत्रिक संस्थाएं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्य बातें

- पाक प्रायोजित आतंकवाद एक सुनियोजित रणनीति और उसकी पुरानी कुंठा है
- भारत ने अपनी सैन्य क्षमता, राष्ट्रीय संकल्प, नैतिक बल और राजनीतिक कौशल प्रदर्शित किया
- पाकिस्तान अगर फिर कोई नापाक हरकत की कोशिश करता है, तो हम और अधिक कठोर और निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार
- जो लोग भारत को हज़ार घाव देने का ख्वाब देखते हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है
- सरकार, सशस्त्र बल और लोकतांत्रिक संस्थाएं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को प्रतिबद्ध ■

लोकसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा

'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से आतंकी शिविरों एवं उनके आकाओं का सफाया किया गया: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के मज़बूत, सफल और निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर 29 जुलाई, 2025 को लोक सभा में हुई विशेष चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भाग लेते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों का धर्म पूछकर की गई हत्या की घोर निंदा करते हुए मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की

केन्द्रीय गृह मंत्री ने लोक सभा को कल कश्मीर के दाचीगाम में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान 'ऑपरेशन महादेव' में तीन आतंकवादियों – सुलेमान, अफ़गान और जिब्रान – को मार गिराए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुलेमान लश्कर का 'ए' श्रेणी का कमांडर था जो पहलगाम और गगनगीर में हुए आतंकवादी हमलों में लिप्त था। अफ़गान और जिब्रान भी लश्कर के 'ए' श्रेणी के आतंकवादी थे जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा था और कल ये तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। गृह मंत्री ने सेना के 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को सदन और पूरे देश की ओर से इस सफलता के लिए बधाई दी।

ऑपरेशन महादेव

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई, 2025 को हुई। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल, 2025 को दोपहर 1 बजे हुआ और वे शाम साढ़े 5 बजे श्रीनगर पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को सुरक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी सुरक्षाबल, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल थे और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग सकें और हमने इसकी पुख्ता व्यवस्था की और उन्हें देश से भागने नहीं दिया।

श्री अमित शाह ने सदन को बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहले से ही इन तीन आतंकवादियों को शरण देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि जब इन तीनों आतंकियों के शव श्रीनगर आए तब चार लोगों ने इनकी पहचान कर बताया कि इन्हीं तीनों आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया था।

आतंकियों के आकाओं का खात्मा

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों के आकाओं को ज़मीन में मिलाने का काम किया और कल हमारी सेना और सीआरपीएफ ने उन तीन आतंकियों को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन महादेव' हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बहुत बड़ी साझी कामयाबी है जिसपर देश की 140 करोड़ जनता को नाज़ है। उन्होंने बताया कि आतंकी हमले के बाद वे स्वयं पहलगाम जाकर वहां मृतकों के परिजनों से मिले थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को भेजने वालों को मारा और हमारे सुरक्षाबलों ने उन आतंकियों को भी मार दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसा सबक सिखाया गया है कि आने वाले लंबे समय तक तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा।

आतंकियों को शरण

श्री शाह ने बताया कि पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर आतंकियों के स्केच बनाए गए और 22 जून, 2025 को बशीर और परवेज़ की पहचान की गई, जिन्होंने पहलगाम हमले के अगले दिन आतंकियों को शरण दी थी। उन्होंने कहा कि बशीर और परवेज़ को गिरफ्तार किया गया और इन्होंने खुलासा किया कि 21 अप्रैल, 2025 की रात को 8 बजे तीन आतंकी इनके पास आए थे और उनके पास दो एके 47 और एक एम 4 कार्बाइन राइफल थी। श्री शाह ने सदन को जानकारी दी कि बशीर और परवेज़ की मां ने भी तीनों मारे गए आतंकियों को पहचान लिया है और अब FSL से भी इस बात की पुष्टि हो गई है। उन्होंने कहा कि यही तीनों पहलगाम हमले में शामिल आतंकी थे और इस हमले में इनके पास से मिली 2 एके 47 और एक एम 9 कार्बाइन का उपयोग हुआ था।

सिंधु जल संधि स्थगित

श्री अमित शाह ने लोक सभा को बताया कि 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इन मृतकों में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं उसी वक्त श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे और रात को ही सुरक्षाबलों और सभी एजेंसियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि हमले में शामिल आतंकी देश छोड़कर न भाग सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 और 30 अप्रैल को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल की बैठक में सबसे पहले सिंधु जल संधि को स्थगित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसके बाद अटारी के माध्यम से चल रही एकीकृत जांच चौकी को बंद किया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीज़ा को सस्पेंड कर सभी को पाकिस्तान वापिस भेजने का काम किया गया, पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत रक्षा, सैन्य, नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया गया और उनकी संख्या को 55 से घटाकर 30 किया।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 और 30 अप्रैल को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की। 23 अप्रैल की बैठक में सबसे पहले सिंधु जल संधि को स्थगित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसके बाद अटारी के माध्यम से चल रही एकीकृत जांच चौकी को बंद किया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीज़ा को सस्पेंड कर सभी को पाकिस्तान वापिस भेजने का काम किया गया

पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकाने तबाह

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सात मई को रात 1 बजकर 22 मिनट पर हमारे डीजीएमओ (डीजीएमओ) ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया कि हमने केवल आतंकवादियों के ठिकानों और उनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है जो हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आज देश में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है और अब ऐसा हो नहीं सकता कि वो आकर मारें और हम चुपचाप बैठे रहें और चर्चा करें। श्री शाह ने कहा कि उरी आतंकी हमले के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक की और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर तक अंदर घुसकर आतंकियों के नौ ठिकानों और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को हमने समाप्त कर दिया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि सवाल यह है कि विपक्षी पार्टी के शासनकाल में वर्ष 2005 से 2011 तक आतंकवादियों ने 27 जघन्य हमले किए, जिसमें 1000 के करीब लोग मारे गए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने क्या किया? उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दी कि वह सदन में खड़े होकर देश को बताएं कि तत्कालीन सरकार ने उन आतंकवादी हमलों के खिलाफ क्या कदम उठाए। वे यहां से आतंकवादियों की फोटो और डोजियर पाकिस्तान भेजते रहे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे समय में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वे पाकिस्तान प्रेरित थीं और मुख्यतः वे कश्मीर केन्द्रित रहीं। देश के किसी अन्य हिस्से में 2014 से 2025 तक शायद ही कोई आतंकी घटना हुई। उन्होंने कहा कि यह नरेन्द्र मोदी सरकार है जिसके कारण अब कश्मीर में आतंकवादी नहीं बनते, बल्कि ऐसी स्थिति हो चुकी है कि उन्हें आतंकवादी पाकिस्तान से भेजने पड़ते हैं।

सरकार ने 'जीरो टेरर' प्लान बनाया

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने 'जीरो टेरर' प्लान बनाया है, एरिया डोमिनेशन प्लान बनाया है, मल्टीलेवल डिप्लॉयमेंट किया है, सुरक्षा जेलें बनाई हैं, 98 प्रतिशत ट्रायल अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हो रही हैं। हमने संचार के साधन बनाए हैं और 702 फोन विक्रेताओं को जेल में डाला है और 2666 सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे जवान माइनस 43 डिग्री तापमान में पहाड़ पर और नदियों-नालों के पास रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। कोई घुस गया तो वो बचेगा नहीं, हम उसे या तो गिरफ्तार करेंगे या तो एनकाउंटर में मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि पोटा का विरोध करने वालों को नरेन्द्र मोदी जी की आतंकवादी विरोधी नीति पसंद नहीं आएगी, आतंकी का बचाव करके वोट बैंक बनाने वालों को यह नीति पसंद नहीं आएगी। यह नरेन्द्र मोदी सरकार है, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। ■

विरासत का हस्तांतरण: मोदी जी ने वाजपेयी जी के 'विकसित भारत' के स्वप्न को कैसे साकार किया

डॉ. के. लक्ष्मण

गतांक से आगे...

वाजपेयी जी के दृष्टिकोण को साकार करना: श्री नरेन्द्र मोदी एवं 'विकसित भारत 2047' का रोडमैप

अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगभग एक दशक की सरकार के बाद 2014 में नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अपनी अद्भुत दूरदर्शिता एवं गतिशीलता के साथ उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहां अटल जी ने छोड़ा था। उन्होंने न केवल वाजपेयी जी द्वारा स्थापित मूलभूत आदर्शों को आत्मसात किया, बल्कि उन्हें नई उंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि हमारे आदरणीय एवं प्रशंसनीय नेता के दृष्टिकोण को न केवल याद रखा गया, बल्कि आधुनिक भारत में उन्हें पूरी तरह साकार भी किया जा रहा है।

मोदी सरकार के आगमन के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रतीकात्मक 'मशाल' एक दूरदर्शी नेता से दूसरे दूरदर्शी नेता के हाथों में चली गई तथा अब यह मशाल और भी तेजी से प्रज्ज्वलित हो रही है, प्रगति और समावेशिता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मोदी जी का नेतृत्व एक अत्यंत शक्तिशाली निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है, जो वाजपेयी जी के ब्लूप्रिंट यानी पैमाने, गति और बेहतर तकनीकी एकीकरण के साथ आगे बढ़ रहा है।

बुनियादी ढांचे एवं कनेक्टिविटी में एक बड़ी छलांग

बुनियादी ढांचे के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए वाजपेयी जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने इसे अभूतपूर्व पैमाने एवं एक महत्वाकांक्षा के साथ अपनाया। उदाहरण के लिए 'भारतमाला परियोजना' हमारी 'स्वर्णिम चतुर्भुज' योजना का एक सीधा एवं व्यापक विस्तार है, जिसका उद्देश्य 83,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का विकास करना है, जिसमें आर्थिक गलियारे, अंतरराज्य-गलियारे और कई फीडर मार्ग शामिल हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सड़कों की दक्षता, सीमा और अंतरराष्ट्रीय सड़कों, बंदरगाहों एवं तटीय संपर्क सड़कों तथा कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी में सुधार करना भी है।

> मोदी सरकार के आगमन के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रतीकात्मक 'मशाल' एक दूरदर्शी नेता से दूसरे दूरदर्शी नेता के हाथों में चली गई तथा अब यह मशाल और भी तेजी से प्रज्ज्वलित हो रही है, प्रगति और समावेशिता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मोदी जी का नेतृत्व एक अत्यंत शक्तिशाली निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है, जो वाजपेयी जी के ब्लूप्रिंट यानी पैमाने, गति और बेहतर तकनीकी एकीकरण के साथ आगे बढ़ रहा है

इसी प्रकार सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण एवं सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है। इसका लक्ष्य भारत के जलमार्ग एवं तटरेखा में सुधार लाना है। यह वाजपेयी जी की आर्थिक समझ का स्वाभाविक विस्तार है।

बंदरगाहों एवं सड़कों के अलावा वर्तमान सरकार ने समर्पित माल ढुलाई गलियारों, हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार, हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि तथा नए हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर तेजी से काम किया है। ये सभी मिलकर एक निर्बाध, एकीकृत राष्ट्रीय परिवहन ग्रिड बनाने में योगदान दे रहे हैं।

मोदी सरकार ने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी जोर दिया है, जो वाजपेयी जी के आधुनिकीकरण के प्रयासों की याद दिलाता है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल लोगों को जोड़ रही है और उनके जीवन को अभूतपूर्व रूप से प्रभावित कर रही है। लेकिन ये पहल सिर्फ लोगों को जोड़ने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिकों को सशक्त बनाते हुए शासन में बदलाव लाने का भी प्रयास करती हैं।

जैम (जन-धन, आधार, मोबाइल) त्रिमूर्ति ने एक मजबूत सार्वजनिक ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत हम डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) का प्रयोग कर, भ्रष्टाचार और लीकेज पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे है। यह वाजपेयी जी के सुशासन एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रकटीकरण है।

भारतनेट परियोजना, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर (हाई-स्पीड इंटरनेट) से जोड़ना है, डिजिटल डिवाइड को पाटने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आधुनिक भारत के लाभ दूरस्थतम गांवों तक भी पहुंचें।

हाशिए पर पड़े लोगों का सशक्तीकरण: अंत्योदय की पहल

अंत्योदय (अंतिम व्यक्ति का उत्थान) के लिए वाजपेयी जी के कार्य को हमारे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाया है। 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के साथ आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा बन गयी है। यह योजना गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी चिकित्सा उपचार प्रदान करने के साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि हाशिए पर पड़े एवं सबसे कमजोर लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वित्तीय समावेशन एक और आधारशिला रही है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने लाखों परिवारों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा है और उनकी पहुंच बैंक खाते, डेबिट कार्ड, ऋण एवं बीमा तक सुनिश्चित की है। इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हमारे नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाकर एवं अर्थव्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार साबित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी पहलों ने ग्रामीण महिलाओं को मुफ़्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए और सार्वभौमिक स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग किया है। ऐसे ही स्वच्छ भारत अभियान ने हाशिए पर पड़े लोगों के जीवन स्तर और सम्मान में प्रत्यक्ष रूप से सुधार किया है। यह उनके सशक्तीकरण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपनी दृढ़ कूटनीति का परिचय दिया है एवं वैश्विक मंच पर भारत का कद बढ़ाया है जो वाजपेयी जी की सिद्धांतबद्ध विदेश नीति की काफी याद दिलाता है। 'एक्ट ईस्ट' और 'नेबरहुड फर्स्ट' जैसी पहलों ने भारत की रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है जो मोदी जी की सक्रिय विदेश नीतियों की पहचान है। रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे पर निर्णायक कार्रवाई जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, भारत के हितों की रक्षा के लिए उनकी सच्ची दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुच्छेद 370 को निरस्तीकरण, जो पार्टी की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा थी, ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीतिक स्वायत्तता पर प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ रुख को प्रदर्शित किया है।

संकट के समय में लचीलापन एवं सुशासन

कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार की त्वरित एवं व्यापक प्रतिक्रिया ने सुशासन तथा जन-केंद्रित नीतियों की विरासत को दर्शाया है। स्वदेशी टीकों के तीव्र विकास एवं उपयोग से लेकर व्यापक टीकाकरण अभियान तक और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने से लेकर आर्थिक राहत पैकेजों तक, प्रशासन ने संकट के समय में संयम और जन कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। डिजिटल सुधारों पर निरंतर जोर, जैसे कि डिजिटल लेन-देन में क्रांति लाने वाला यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और टीकाकरण प्रबंधन के लिए कोविन प्लेटफ़ॉर्म, कुशल और पारदर्शी शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की क्षमता को दर्शाता है, जो एक आधुनिक और प्रभावी राज्य के लिए वाजपेयी जी के दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष विस्तार है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपनी दृढ़ कूटनीति का परिचय दिया है एवं वैश्विक मंच पर भारत का कद बढ़ाया है जो वाजपेयी जी की सिद्धांतबद्ध विदेश नीति की काफी याद दिलाता है। 'एक्ट ईस्ट' और 'नेबरहुड फर्स्ट' जैसी पहलों ने भारत की रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है जो मोदी जी की सक्रिय विदेश नीतियों की पहचान है

आदर्शों का अनुकरण: मेरी संसदीय भूमिका

अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर काम करने का विशिष्ट सौभाग्य प्राप्त करने और अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में सेवा करने के बाद यह स्पष्ट है कि हमारी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग है। नीतियों का विकास और शासन के प्रति दृष्टिकोण समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप ढले हैं, फिर भी हमारी विचारधारा की गहरी जड़ों और हमारे संस्थापक नेताओं के दृष्टिकोण को कभी नजरअंदाज नहीं किया गया है।

एक सांसद के रूप में मैं हर दिन देखता हूं कि कैसे वाजपेयी जी के दृष्टिकोण की भावना वर्तमान प्रशासन के कार्यों में व्याप्त है। चाहे स्वास्थ्य सेवा सुधार हो, शिक्षा नीतियों या सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी बहस हो, यह सभी इस बात पर जो देते है कि योजनाओं का लाभ सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचें। यह केवल आंकड़ा नहीं है; यह मानवीय पहलू के बारे में है, यह एक ऐसा सबक है जो मैंने वाजपेयी जी के शासन से सीखा है।

राष्ट्रीय अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता एक और सिद्धांत है जिसे नए जोश के साथ आगे बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले विधायी उपायों से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की संप्रभुता को स्थापित करने वाले कूटनीतिक प्रयासों तक, हर कदम हमारे राष्ट्र की एकता की रक्षा और उसे बनाए रखने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित है। यह वाजपेयी जी के राष्ट्रीय गौरव के प्रति दृढ़ संकल्प एवं उनके रणनीतिक संकल्प को प्रतिध्वनित करता है।

इसके अलावा, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के बीच संतुलन एक विशिष्ट

वाजपेयी जी द्वारा रखी गई नींव पर अब मोदी जी ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे प्रगति की एक ऐसी इमारत खड़ी हो रही है जो सभी भारतीयों के लिए एक बेहतर और उज्ज्वल भविष्य का वादा करती है। हम सभी लोग, एक राष्ट्र के रूप में एक सशक्त और सामंजस्यपूर्ण भारत के भव्य स्वप्न को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। एक ऐसा स्वप्न जो हमारे समृद्ध अतीत के अनुरूप हो और साथ ही भविष्य की असीम संभावनाओं को साहसपूर्वक अपनाए

विशेषता बनी हुई है। राष्ट्रवाद के बारे में पार्टी का दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से समावेशी है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए साझा राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर आधारित एक सामूहिक पहचान को बढ़ावा देता है। यह एक सूक्ष्म दृष्टिकोण है, जिसका वाजपेयी जी ने सद्भाव और आम सहमति पर जोर देकर समर्थन किया था और जिसे मोदी जी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में व्यक्त करते रहते हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसी परिवर्तनकारी पहल, जिसने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सुव्यवस्थित किया, सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व वृद्धि, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार और विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से डिजिटल सशक्तीकरण- ये सभी केवल छिटपुट उपलब्धियां नहीं हैं, ये मूलतः वाजपेयी जी के दूरदर्शी रोडमैप की मूर्त अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार करने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और सशक्त रूप से क्रियान्वित किया गया। मुझे इस सतत् यात्रा में योगदान देने पर गर्व है, यह देखकर कि कैसे दशकों पहले बोए गए बीज अब एक जीवंत, आधुनिक भारत के रूप में फल-फूल रहे हैं।

यात्रा निर्बाध जारी है

भाजपा सांसद के रूप में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की समृद्ध विरासत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील एवं परिवर्तनकारी नेतृत्व का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसाकि मोदी जी ने कहा है, 'हम साथ-साथ चलते हैं, हम साथ-साथ सोचते हैं, हम साथ-साथ संकल्प करते हैं और हम साथ-साथ इस देश को आगे बढ़ाते हैं।' राष्ट्र निर्माण की इस निरंतर प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनकर मुझे अपार गर्व और कृतज्ञता का अनुभव हो रहा है।

अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूरदर्शी दृष्टिकोण से मोदी जी के '2047 तक विकसित भारत' के दृढ़ संकल्प को साकार करने की दिशा में विरासत का हस्तांतरण, भारत की विकासात्मक कहानी को सामने लाने में एक निर्बाध एवं शक्तिशाली निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है।

आज, भारत वैश्विक मंच पर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर निरंतर अग्रसर है। भारत ने स्वयं को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है जो अपने लोकाचार एवं विकास यात्रा में समावेशी है, उत्तरोत्तर आधुनिक होता जा रहा है और अपनी आकांक्षाओं में 'अनेकता में एकता' के दृष्टिकोण को आत्मसात करते हुए उल्लेखनीय रूप से एकजुट है। यह जीवंतता इस बात का प्रमाण है कि वाजपेयी जी के एक सशक्त, समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भारत के सपने न केवल आज भी कायम हैं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सक्रिय रूप से फल-फूल भी रहे हैं।

वाजपेयी जी द्वारा रखी गई नींव पर अब मोदी जी ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे प्रगति की एक ऐसी इमारत खड़ी हो रही है जो सभी भारतीयों के लिए एक बेहतर और उज्ज्वल भविष्य का वादा करती है। हम सभी लोग, एक राष्ट्र के रूप में एक सशक्त और सामंजस्यपूर्ण भारत के भव्य स्वप्न को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। एक ऐसा स्वप्न जो हमारे समृद्ध अतीत के अनुरूप हो और साथ ही भविष्य की असीम संभावनाओं को साहसपूर्वक अपनाए। ■

(लेखक भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद हैं)

पिछले 6 वित्तीय वर्षों में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए

डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव किया है, खासकर वंचित समुदायों के लिए

पिछले 6 वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। पिछले 6 वर्षों में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिनकी राशि 12,000 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने 28 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

सरकार देश में डिजिटल भुगतान को अपनाने की दर बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), फिनटेक, बैंकों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें टियर-2 और टियर-3 शहर भी शामिल हैं। आरबीआई ने टियर-3 से 6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में डिजिटल भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए 2021 में एक पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) की स्थापना की है। 31 मई, 2025 तक पीआईडीएफ के माध्यम से लगभग 4.77 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट तैनात किए गए हैं।

डिजिटल भुगतानों के बढ़ते चलन ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव किया है, खासकर वंचित और वंचित समुदायों के लिए। यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध और पता लगाने योग्य लेनदेन को सक्षम करके डिजिटल भुगतानों ने व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक मज़बूत वित्तीय पहचान बनाई है। यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने छोटे विक्रेताओं और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं सहित नागरिकों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने, नकदी पर निर्भरता कम करने और औपचारिक आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में सक्षम बनाया है। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' के लिए कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को दी स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई को 15वें वित्त आयोग चक्र (एफसीसी) (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' (पीएमकेएसवाई) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति दी।

इसमें (i) बजट घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजना— एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (आईसीसीवीएआई) के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और घटक योजना— खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसक्यूएआई) के अंतर्गत एनएबीएल मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल) की स्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपये तथा (ii) 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए 920 करोड़ रुपये शामिल हैं।

प्रस्तावित 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के कार्यान्वयन से इन इकाइयों के अंतर्गत विकिरणित खाद्य उत्पादों के प्रकार के आधार पर प्रतिवर्ष 20 से 30 लाख मीट्रिक टन तक की कुल संरक्षण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है। निजी क्षेत्र के तहत प्रस्तावित 100 एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना से खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ■

ई-श्रम पोर्टल पर 30.95 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत

30.95 करोड़ से अधिक असंगठित (22 जुलाई, 2025 तक) श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने 28 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उल्लेखनीय है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरुआत की। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है।

अब तक विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है ताकि ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा अथवा कौशल विकास कार्यक्रमों के लाभ और पहुंच प्रदान की जा सके ■

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन

कर्तव्य भवन 'विकसित भारत' की नीतियों और दिशा का मार्गदर्शन करेगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छह अगस्त को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-3 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत एक के बाद एक आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों का गवाह बन रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कर्तव्य भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। उन्होंने कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर सभी नागरिकों को बधाई दी और इसके निर्माण में लगे इंजीनियरों और श्रमजीवियों का भी आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन-3 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्रांति का अगस्त महीना 15 अगस्त से पहले एक और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण उपलब्धि लेकर आया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत एक के बाद एक आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों का गवाह बन रहा है। श्री मोदी ने नई दिल्ली का उल्लेख करते हुए हाल के अवसंरचनात्मक स्थलों— कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नया रक्षा कार्यालय परिसर, भारत मंडपम, यशोभूमि, शहीदों को समर्पित राष्ट्रीय समर स्मारक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और अब कर्तव्य भवन को सूचीबद्ध किया। इस बात पर बल देते हुए कि ये केवल नई इमारतें या नियमित बुनियादी ढांचा नहीं हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल में 'विकसित भारत' को आकार देने वाली नीतियां इन्हीं संरचनाओं में तैयार की जाएंगी और आने वाले दशकों में राष्ट्र की दिशा इन संस्थानों से निर्धारित की जाएगी।

यह बताते हुए कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय वर्तमान में पूरी दिल्ली में 50 विभिन्न स्थानों से काम कर रहे हैं, श्री मोदी ने कहा कि इनमें से कई मंत्रालय किराए के भवनों से काम कर रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि अकेले किराये की लागत पर वार्षिक व्यय 1,500 करोड़ रुपये की राशि चौंका देने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी राशि केवल बिखरे हुए सरकारी कार्यालयों के लिए किराए पर खर्च की जा रही है। एक और चुनौती पर ध्यान देते हुए उन्होंने इस विकेंद्रीकरण के कारण कर्मियों की लॉजिस्टिक आवाजाही के बारे में कहा कि अनुमानित 8,000 से 10,000 कर्मचारी मंत्रालयों के बीच प्रतिदिन यात्रा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है, अत्यधिक धन व्यय होता है और यातायात की भीड़ बढ़ जाती है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि समय की हानि का सीधा असर प्रशासनिक दक्षता पर पड़ता है।

21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक इमारतों की आवश्यकता

इस बात पर बल देते हुए कि 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक इमारतों की आवश्यकता है, श्री मोदी ने ऐसी संरचनाओं की आवश्यकता का उल्लेख किया जो प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और सुविधा के मामले में अनुकरणीय हों। यह बताते हुए कि कर्तव्य पथ के आसपास समग्र दृष्टि के साथ कर्तव्य भवन जैसे बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला कर्तव्य भवन पूरा हो चुका है, लेकिन कई अन्य कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से प्रगति पर है।

श्री मोदी ने कहा, "भव्य कर्तव्य भवन और नए रक्षा परिसरों सहित अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं न केवल भारत की गति का प्रमाण हैं, बल्कि इसकी वैश्विक दृष्टि का प्रतिबिंब भी हैं।" ■

प्रधानमंत्री ने वाराणसी से 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान की 20वीं किस्त जारी की

हमारी सरकार किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो अगस्त को 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार वाराणसी का दौरा किया। इस अवसर पर उपस्थित भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सावन के पावन माह में वाराणसी के परिवारों से मिलकर उनसे अपनी हार्दिक भावनाएं व्यक्त कीं। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को याद करते हुए कहा कि इसमें 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। श्री मोदी ने पीड़ित परिवारों, विशेषकर इस त्रासदी से प्रभावित बच्चों और बेटियों के दुःख को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का उनका वादा पूरा हुआ है

उपस्थित जनसमूह को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बताया कि हाल के दिनों में वे वाराणसी में शिव भक्तों की दिव्य छवियां देख रहे थे, विशेषकर सावन के पहले सोमवार को, जब तीर्थयात्री बाबा विश्वनाथ का पवित्र जलाभिषेक करने के लिए निकलते हैं। उन्होंने गौरी केदारनाथ से अपने कंधों पर पवित्र गंगाजल लाते यादव बंधुओं के मनोरम दृश्य का उल्लेख करते हुए इसे बेहद मनमोहक बताया।

भारत के तमिलनाडु में शैव परंपरा के एक प्राचीन ऐतिहासिक केंद्र गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और एक हज़ार वर्ष प्राचीन स्मारक की कुछ दिन पहले की अपनी यात्रा का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध राजा राजेंद्र चोल ने करवाया था, जो उत्तर और दक्षिण को प्रतीकात्मक रूप से एक करने के लिए उत्तर भारत से गंगाजल लेकर आए थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज, काशी-तमिल संगमम जैसी पहलों के माध्यम से उस विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गंगईकोंडा चोलपुरम की अपनी हाल की यात्रा के दौरान वे अपने साथ गंगाजल लेकर गए थे और मां गंगा के आशीर्वाद से अत्यंत पवित्र वातावरण में पूजा संपन्न हुई। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर देश में एकता की भावना को जगाते हैं, जिससे ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों को सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की एकता 'ऑपरेशन सिंदूर' की ताकत बनी।

2,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

वाराणसी में आयोजित किसान महोत्सव के भव्य आयोजन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देशभर के 10 करोड़ किसान भाई-बहनों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के दौरान 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।

श्री मोदी ने बताया कि अब तक 3.75 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। अकेले उत्तर प्रदेश

में लगभग 2.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें इस योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी के किसानों को लगभग 900 करोड़ रुपये मिले हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: जो क्षेत्र जितना पिछड़ा होगा, उसे उतनी ही ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी

'जो क्षेत्र जितना पिछड़ा होगा, उसे उतनी ही ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी' के विकास मंत्र को दोहराते हुए श्री मोदी ने घोषणा की कि इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने एक बड़ी नई पहल- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना- को स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा कि हमारी सरकार किसानों के जीवन में बदलाव लाने, उनकी आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है।

श्री मोदी ने स्वीकार किया कि मौसम हमेशा से किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है; चाहे वह अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो या पाला। किसानों को ऐसी अनिश्चितताओं से बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को अब तक 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का निपटान प्राप्त हो चुका है।

जो कोई भी भारत पर हमला करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महादेव की नगरी में विकास और जनकल्याण के लिए अनेक पहल की गई हैं। उन्होंने शिव के अर्थ पर विचार करते हुए कहा कि शिव 'कल्याण' के प्रतीक हैं, लेकिन आतंक और अन्याय का सामना करने पर वे प्रचंड रुद्र रूप भी धारण करते हैं। श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस रुद्र रूप को देखा और घोषणा की, "जो कोई भी भारत पर हमला करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह पाताल लोक में ही क्यों न हो।"

श्री मोदी ने उन दृश्यों का उल्लेख किया, जिनमें दिखाया गया था कि कैसे भारतीय ड्रोनों ने सटीक निशाना साधते हुए आतंकवादी मुख्यालयों को खंडहर में बदल दिया। उन्होंने कहा कि कई पाकिस्तानी हवाई अड्डे अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि जहां एक ओर आतंक के आका विलाप कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये दल आतंकवादियों की स्थिति पर भी शोक मना रहे हैं।

श्री मोदी ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त होने के लिए विपक्ष की कड़ी निंदा की। उन्होंने संसद में विपक्षी नेताओं द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों का हवाला देते हुए और उनकी आलोचना करते हुए पूछा कि क्या भारत को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले इंतजार करना चाहिए? श्री मोदी ने जनता को याद दिलाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान आतंकवादियों को क्लीन चिट दी थी और बम विस्फोटों में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए थे। उन्होंने कहा कि अब ये दल आतंकवादियों के सफाए और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही परेशान हैं। वाराणसी की पावन धरती से प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि यह एक नया भारत है, एक ऐसा भारत जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव बनना भी जानता है।

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। ■

'पीएम-किसान के तहत अब तक किसानों को 3.89 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित हुए'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर देश के 9.70 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर करने पर भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री राजकुमार चाहर ने 02 अगस्त, 2025 को एक प्रेस कांफ्रेंस कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश के करोड़ों किसानों एवं भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से धन्यवाद व साधुवाद दिया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 3.89 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। 18 जून, 2024 को 19वीं किस्त के रूप में 9.26 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि भेजी गई थी।

भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री राजकुमार चाहर ने कहा कि 1 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी, इस योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य एवं उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कृषि आदानों की खरीद में सभी किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, जो अनुमानित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के लिए भी है। इस योजना के द्वारा लगातार हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से सबल हो रहे हैं और कर्ज के मकड़जाल से निकालने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में किसानों के हितों में लिए गए निर्णय के लिए भी विशेष आभार प्रकट किया। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को और सशक्त बनाने के लिए इसके बजट में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। ■

एनईपी के पांच वर्ष: विकसित भारत की नींव

धर्मेंद्र प्रधान

2020 में हमने केवल एक नीति को जारी करने से कहीं अधिक किया, हमने अपने प्राचीन आदर्श को पुनर्जीवित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ शिक्षा को एक बार फिर राष्ट्र-निर्माण के केंद्र में रखा गया और भविष्य की संभावनाओं को आकार देने के लिए हमारी सभ्यतागत बुद्धिमत्ता का सहारा लिया गया। देश के इतिहास की सबसे अधिक भागीदारी वाली नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में से एक के माध्यम से तैयार एवं (दिवंगत) डॉ. के. कस्तूरीरंगन की दूरदर्शिता द्वारा निर्देशित, जिनके योगदान का हम गहरा सम्मान करते हैं, एनईपी 2020 केवल एक नीति दस्तावेज नहीं था, यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में निहित एक दूरदर्शी रोडमैप था। इसे रटने के बजाय सीखने, कठोर संरचनाओं और भाषाई पदानुक्रमों की सीमाओं से मुक्त किया गया है। इसने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का मंच तैयार किया जो समग्र, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार है, एक ऐसी शिक्षा जो प्रत्येक शिक्षार्थी को तेजी से बदलती दुनिया में फलने-फूलने के लिए सशक्त बनाती है।

पांच साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिवर्तनकारी प्रभाव न केवल नीतिगत गलियारों में, बल्कि कक्षाओं, परिसरों और समुदायों में भी दिखाई दे रहा है। इसने भारत की शिक्षा प्रणाली की संरचना और भावना, दोनों को पुनर्परिभाषित किया है।

आज, एनईपी की छाप शुरुआती कक्षाओं में देखी जा सकती है जहां रटने की आदत की जगह आनंदपूर्ण, खेल-आधारित शिक्षा दी जा रही है; उन स्कूलों में जहां बच्चे अपनी मातृभाषा में धाराप्रवाह पढ़ते हैं; व्यावसायिक प्रयोगशालाओं में जहां कक्षा 6 के छात्र व्यावहारिक कौशल विकसित करते हैं; और उन अनुसंधान केंद्रों में जहां भारत की ज्ञान प्रणालियां अत्याधुनिक विज्ञान के साथ संवाद करती हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी (STEM) क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान, भारतीय संस्थानों की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति, विविधता को अपनाने वाली समावेशी कक्षाओं और इस नए विश्वास में परिलक्षित होता है कि सीखना एक आजीवन प्रयास होना चाहिए।

देश के इतिहास की सबसे अधिक भागीदारी वाली नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में से एक के माध्यम से तैयार एवं (दिवंगत) डॉ. के. कस्तूरीरंगन की दूरदर्शिता द्वारा निर्देशित, जिनके योगदान का हम गहरा सम्मान करते हैं, एनईपी 2020 केवल एक नीति दस्तावेज नहीं था, यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में निहित एक दूरदर्शी रोडमैप था। इसे रटने के बजाय सीखने, कठोर संरचनाओं और भाषाई पदानुक्रमों की सीमाओं से मुक्त किया गया है

हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सीखने की नींव को फिर से मज़बूत करना रही है। निपुण भारत मिशन, यह सुनिश्चित करके कि सभी बच्चे कक्षा 2 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर लें, सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार के साथ सकारात्मक प्रभाव लाने में सहायक रहा है, जैसाकि एनईपी 2020 में परिकल्पित है। निपुण भारत की सफलता, असर 2024 और परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में परिलक्षित होती है, जिसने कक्षाओं को केवल अनुपालन ही नहीं, बल्कि जिज्ञासा और समझ का स्थान बना दिया है।

विद्या प्रवेश और बालवाटिकाओं के संस्थागतकरण जैसी पहलों ने देश भर में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के एकीकरण के लिए एक मज़बूत आधारशिला रखी है।

नए जमाने की पाठ्यपुस्तकों का विकास और 22 भारतीय भाषाओं में जादुई पिटारा और ई-जादुई पिटारा की शुरुआत, इसे और मजबूती प्रदान कर रही है। 14 लाख से ज़्यादा शिक्षकों ने निष्ठा प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और दीक्षा जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने देश भर में उच्च-गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों तक पहुंच का विस्तार किया है।

नीति का भाषा पर ध्यान केंद्रित करना भी उतना ही आधारभूत है। एनईपी ने माना है कि भाषा कोई बाधा नहीं, बल्कि सशक्तीकरण का एक सशक्त माध्यम है। 117 भाषा-आधारित पाठ्यपुस्तकों के विकास और भारतीय सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने से बहुभाषी, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य बड़े पैमाने पर साकार हो रहा है। ये प्रयास न केवल संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाते हैं, बल्कि बच्चे की सांस्कृतिक पहचान को भी सुदृढ़ करते हैं। भारतीय भाषा पुस्तक योजना और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल डिपोजिटरी जैसी पहल भाषाई और सभ्यतागत शिक्षा तक पहुंच को और अधिक लोकतांत्रिक बनाएंगी।

इसके बाद, एनईपी ने छात्रों में जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को जगाने के लिए नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की पुनर्कल्पना की है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) और कक्षा 1-8 के लिए नई पाठ्यपुस्तकें पहले से ही मौजूद हैं, जो विभिन्न विषयों में योग्यता-आधारित शिक्षा और एकीकरण को बढ़ावा देती हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिए ब्रिज कार्यक्रम और प्रेरणा जैसी अनुभवात्मक शिक्षण पहल यह सुनिश्चित कर रही हैं कि छात्र अभिभूत न हों, बल्कि प्रत्येक चरण में उन्हें सहयोग मिले।

समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री पोषण जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जीवंत प्रयासों से भारत ने लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त कर लिया है, प्राथमिक स्तर पर जीईआर 91.7 प्रतिशत तक पहुंच गया है और माध्यमिक स्तर पर भी इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अब स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

एनईपी के माध्यम से वंचित आबादी तक भी पहुंच बनी है। वंचित समूहों की 7.12 लाख से ज़्यादा लड़कियां 5,138 से ज़्यादा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकित हैं, पीवीटीजी शिक्षार्थियों के लिए 490 से ज़्यादा छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत 692 छात्रावास बनाए गए हैं।

समान पहुंच का विस्तार करने और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करने के ये प्रयास, एनईपी 2020 की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि, स्कूली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को दर्शाते हैं। मज़बूत बुनियादी ढांचे, विकलांगता जांच के लिए प्रशस्त जैसे समावेशी कार्यक्रमों और नए डिजिटल उपकरणों के साथ, स्कूली शिक्षा प्रणाली अधिक लचीली और समावेशी होती जा रही है।

इस परिवर्तन का एक प्रमुख कारक 14,500 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना है। इन आधुनिक, समावेशी और हरित संस्थानों को एनईपी के दृष्टिकोण के अनुरूप आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो अपने क्षेत्रों में नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को उत्प्रेरित करते हुए बुनियादी ढांचे और शिक्षाशास्त्र को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं।

सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए विद्यांजलि प्लेटफ़ॉर्म ने 8.2 लाख से अधिक स्कूलों को 5.3 लाख से अधिक स्वयंसेवकों और 2000 सीएसआर भागीदारों से जोड़ा है, जिससे 1.7 करोड़ छात्र सीधे लाभान्वित हुए हैं। यह जनभागीदारी का एक असाधारण उदाहरण है, जो साझा ज़िम्मेदारी के माध्यम से शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है।

समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री पोषण जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जीवंत प्रयासों से भारत ने लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त कर लिया है, प्राथमिक स्तर पर जीईआर 91.7 प्रतिशत तक पहुंच गया है और माध्यमिक स्तर पर भी इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अब स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है

उच्च शिक्षा में भी बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। कुल नामांकन 3.42 करोड़ से बढ़कर 4.46 करोड़ हो गया है, जो 30.5 प्रतिशत की वृद्धि है। अब सभी छात्राओं में महिलाओं की संख्या लगभग 48 प्रतिशत है, और महिला पीएचडी नामांकन 0.48 लाख से दोगुने से भी अधिक बढ़कर 1.12 लाख हो गया है।

नामांकन में यह वृद्धि, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए, उच्च शिक्षा में समावेशिता की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। महिला जीईआर आवेदक लगातार छह वर्षों से पुरुष से आगे रही है, जो एनईपी के समता दृष्टिकोण का एक प्रमाण है।

इसके समानांतर उच्च शिक्षा के संरचनात्मक ताने-बाने को नया रूप दिया गया है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट (एमईएमई), 21.12 करोड़ से अधिक एपीएएआर आईडी जारी करने वाले अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) की शुरुआत ने अभूतपूर्व लचीलापन और गतिशीलता प्रदान की है। 153 विश्वविद्यालय बहु-प्रवेश और 74 विश्वविद्यालय बहु-निकास विकल्प प्रदान कर रहे हैं, जिससे अब शिक्षा व्यवस्था केवल एक दिशा में नहीं चल रही, बल्कि यह मॉड्यूलर, छात्र-संचालित और भविष्योन्मुखी हो गई है।

इन ढांचों MEME, ABC और NCrF के संचालन ने भारत को ऐसे एकीकृत डिजिटल शैक्षणिक प्रणालियों के माध्यम से आजीवन शिक्षा का समर्थन करने वाले कुछ देशों में से एक बना दिया है।

अनुसंधान और नवाचार पर एनईपी के ज़ोर ने पहले ही लाभ प्रदान किए हैं। भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंक को 81वें से 39वें स्थान पर लाने से लेकर 400 उच्च शिक्षा संस्थानों में 18,000 से अधिक स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेट करने तक, हमारे परिसर तेज़ी से नवाचार केंद्र बन रहे हैं। अनुसंधान एनआरएफ, संशोधित पीएमआरएफ 2.0, और 6,000 करोड़ रुपये की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल, अनुसंधान तक पहुंच को लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और प्रदर्शित करती है।

प्रौद्योगिकी एक प्रेरक शक्ति बनी हुई है। स्वयं और स्वयं प्लस जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने सामूहिक रूप से 5.3 करोड़ से अधिक नामांकन दर्ज किए हैं और 200 से अधिक डीटीएच चैनलों के साथ दीक्षा और पीएम ई-विद्या जैसी पहलों के सहयोग से, देश भर के शिक्षार्थियों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली

सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं।

भारत के डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम की सफलता, जिसमें द्विवार्षिक प्रवेश, दोहरी डिग्री नियमन शामिल हैं, ने उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, अंतःविषयक और उद्योग-प्रासंगिक बना दिया है।

भारत की बढ़ती शैक्षणिक स्थिति अब वैश्विक स्तर पर परिलक्षित हो रही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है, जबकि 2014 में यह संख्या केवल 11 थी। साथ ही, डीकिन, वोलोंगोंग और साउथेम्प्टन जैसे वैश्विक विश्वविद्यालयों ने भारत में अपने परिसर स्थापित किए हैं, जो हमारी बढ़ती विश्वसनीयता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है।

इस परिवर्तनकारी यात्रा का जश्न अखिल भारतीय शिक्षा समागम के माध्यम से मनाया जा रहा है। एनईपी 2020 कभी कोई घोषणा नहीं थी। यह एक उभरता हुआ पुनर्जागरण है, जो शोरगुल से नहीं, बल्कि गहराई से, गति से नहीं, बल्कि पैमाने से चिह्नित है।

फिर भी, हम आगे की राह के प्रति सचेत हैं। हमें अपने परिसरों को हरा-भरा बनाना, महत्वपूर्ण अनुसंधान अवसंरचना का विस्तार करना, अग्रणी प्रौद्योगिकियों में प्रतिभाओं को पोषित करना और प्रत्येक जिले में शिक्षण परिणामों को गहन बनाना जारी रखना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने यह महसूस किया है कि शिक्षा केवल नीति नहीं है, यह हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय निवेश, हमारा नैतिक दिशानिर्देश और भविष्य के लिए हमारा सामूहिक वादा है।

2020 में जो ज्योति प्रज्वलित हुई थी, वह अब हमारी शिक्षा प्रणाली के हर कोने को प्रकाशित कर रही है। लेकिन इसका असली उद्देश्य घरों, हृदयों और क्षितिजों में लाखों और ज्योतियां प्रज्वलित करना है। 'यत्र विद्या, तत्र प्रगति' जहां शिक्षा है, वहां प्रगति है। एक अरब मन, बंधनमुक्त और सशक्त, केवल जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं हैं; वे एक नए भारत का सुपरनोवा हैं।

यह भारत का संकल्प है, जो प्रतिदिन उन बच्चों के उज्ज्वल सपनों में साकार हो रहा है, जिन्हें अब विश्वास है कि वे जड़ों से जुड़े रहते हुए ऊंची उड़ान भर सकते हैं और जो एक विकसित भारत के भाग्य को आकार देंगे। ■

(लेखक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं)

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नई दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति से मुलाकात की

भाजपा को जानें पहल के तहत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 05 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति महामहिम फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर से मुलाकात की।

राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर का स्वागत करते हुए श्री नड्डा ने इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला, जो भारत-फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। उन्होंने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने और संयुक्त डाक स्मारक टिकट जारी करने का स्वागत किया, जो गहरे होते सांस्कृतिक एवं राजनयिक संबंधों को दर्शाता है।

श्री नड्डा ने भाजपा की व्यापक संगठनात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाला और 'भाजपा को जानें' पहल के तहत इसकी संरचना और कार्यशैली की जानकारी साझा की। उन्होंने आपसी संबंधों

भाजपा को जानें पहल

को मजबूत करने के लिए फ़िलीपींस की फेडरल पार्टी (पीएफपी) और भाजपा के बीच प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रमुख पहलों विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण और विदेश नीति आदि का भी उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स में अधिक सहयोग के अवसरों पर चर्चा की, जहां भारत फिलीपींस का एक प्रमुख भागीदार है।

इस बैठक में श्री नड्डा के साथ भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति महामहिम श्री मार्कोस, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर थे। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद से यह राष्ट्रपति मार्कोस की पहली भारत यात्रा थी। ■

स्वदेशी के मंत्र से 'आत्मनिर्भर' होगा भारत

शिवप्रकाश

भारत के साथ टैरिफ समझौते में अमेरिका की ओर से बनाए जा रहे दबाव के तहत 25 प्रतिशत का टैरिफ न सिर्फ अतार्किक है, बल्कि भारत के ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था व स्वावलंबन पर सीधा हमला है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'स्वदेशी' और 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान अब सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक जवाब है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सिर्फ खेतों और डेयरी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। भारत का यह एक सामाजिक आर्थिक ढांचा है जिसमें छोटे किसान, महिला स्व-सहायता समूह, सहकारी समितियां और पारंपरिक उत्पादन श्रृंखला शामिल हैं। भारत के 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं जिनकी जोत दो हेक्टेयर से भी कम है। देश की आठ करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं और भूमिहीन किसान शामिल हैं। यह पूरा समूह बेहद संवेदनशील है जिसकी आजीविका के लिए सरकार पूरा सहयोग व समर्थन देती है। इतनी बड़ी जनसंख्या का पूरा ढांचा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), सब्सिडी और सीमा शुल्क पर निर्भर करता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी कृषि व डेयरी के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। टैरिफ संरचना की रक्षा करना, स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मज़बूत करना, किसान उत्पादक संगठन, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग इकाइयों को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, पोषण और पारंपरिक कृषि विविधता की रक्षा करने के साथ ग्रामीण जीवन और आजीविका की सुरक्षा करने के लिए सरकार सभी प्रकार से प्रतिबद्ध है।

भारत के साथ टैरिफ समझौते में अमेरिका की ओर से बनाए जा रहे दबाव के तहत 25 प्रतिशत का टैरिफ न सिर्फ अतार्किक है बल्कि भारत के ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था व स्वावलंबन पर सीधा हमला है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'स्वदेशी' और 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान अब सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक जवाब है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सिर्फ खेतों और डेयरी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। भारत का यह एक सामाजिक आर्थिक ढांचा है जिसमें छोटे किसान, महिला स्व-सहायता समूह, सहकारी समितियां और पारंपरिक उत्पादन श्रृंखला शामिल हैं। भारत के 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं जिनकी जोत दो हेक्टेयर से भी कम है। देश की आठ करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं

इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने काशी प्रवास में देश की जनता से स्वदेशी का नारा बुलंद किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया ने स्वदेशी हथियारों की ताकत का अनुभव किया है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ताकत कहा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और आशंका का वातावरण है। इस अस्थिरता से उबारने के लिए सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण की नीति अपना रहे हैं। ऐसे में भारत अलग कैसे रह सकता है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर हमें भी अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति सजग रहते हुए किसानों, लघु उद्योगों और नौजवानों के रोजगार के प्रति सजग रहना होगा। तीसरी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दलगत भाव से ऊपर उठकर समस्त दल, प्रबुद्ध नागरिकों और समाज को स्वदेशी के ही मंत्र को उद्घोष करना चाहिए। हम स्वदेशी को अपनाएं और स्वदेशी को बढ़ाएं।

गत दशक में भारत की अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर प्रगति के शिखर पर जा रही है। वर्ष 2013- 2014 में हम 11 वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे जो आज चौथे नंबर पर है , और अब तीव्र गति से तीसरे नंबर की ओर बढ़ रहे है। हमारी विकास दर 6.4 % की गति से बढ़ रही है। रक्षा, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में भारत का प्रभाव बढ़ा है। विश्व बाजार में भी भारत की भागीदारी भी बढ़ी है। हमारी गरीब

कल्याण की योजनाओं के कारण 24 करोड़ से अधिक गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ढांचागत विकास सहित भारत ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। हमारी मूलभूत सुविधाओं का स्तर विश्व स्तरीय हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम भोलेनाथ को पूजते भी हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी सुरक्षा के लिए कालभैरव भी बन जाते हैं। बढ़ती आर्थिक प्रगति, सक्षम सुरक्षा नीति एवं बढ़ता भारत का वैश्विक प्रभाव दुनिया के देशों में भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न कर रहा है।

अमेरिका की कृषि व्यवस्था औद्योगिक, सब्सिडी-समर्थित और बड़े पैमाने वाली है। इसके मुकाबले भारत में कृषि क्षेत्र में छोटी जोत वाले किसान शामिल है। भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या लगभग 55% है जो बहुतांश गांव में रहती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि क्षेत्र का 15% योगदान है। भारत में खेती की सफलता पूरी तरह मौसम की अनिश्चितता पर निर्भर है। श्रम-आधारित व्यवस्था पर टिकी भारत की खेती की तुलना अमेरिका की खेती से नहीं की जा सकती है। ऐसे में अमेरिका व भारत जैसे देश परस्पर समान टैरिफ पर नहीं आ सकते हैं। भारत का कपड़ा, खाद्यान्न, चीनी, डेयरी एवं मत्स्य व्यवसाय कृषि के साथ ही जुड़ता है। कृषि व डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अमेरिका के लिए खोलने की जिद बेमानी होगी। यदि ऐसा हुआ तो अमेरिकी सस्ते डेयरी उत्पादों से भारतीय बाजार पट जाएगा। महिलाओं के स्व-सहायता समूह, जैसे अमूल जैसी सहकारी संस्थाएं आर्थिक संकट में पड़ जाएंगी। भारतीय किसानों के उत्पादों की कीमतें बाजार में कौड़ियों के भाव बिकने को मजबूर होंगी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संकट, बेरोजगारी, पलायन और असंतोष शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गत दशक में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं। पिछले एक दशक में कृषि बजट में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जो बजट 2013- 2014 में 21,933 करोड़ रुपए की तुलना में 2023-2024 में 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गया। सहकारिता क्षेत्र भी भारत में महिलाओं एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली करने में जुटा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि एवं कृषक कल्याण, महिला सुरक्षा, डेयरी उद्योगों का संरक्षण एवं सहकारिता का पोषण यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। जिसका आह्वान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है।

अमेरिका की कृषि व्यवस्था औद्योगिक, सब्सिडी-समर्थित और बड़े पैमाने वाली है। इसके मुकाबले भारत में कृषि क्षेत्र में छोटी जोत वाले किसान शामिल है। भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या लगभग 55% है जो बहुतांश गांव में रहती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि क्षेत्र का 15%योगदान है। भारत में खेती की सफलता पूरी तरह मौसम की अनिश्चितता पर निर्भर है। श्रम-आधारित व्यवस्था पर टिकी भारत की खेती की तुलना अमेरिका की खेती से नहीं की जा सकती है। ऐसे में अमेरिका व भारत जैसे देश परस्पर समान टैरिफ पर नहीं आ सकते हैं। भारत का कपड़ा, खाद्यान्न, चीनी, डेयरी एवं मत्स्य व्यवसाय कृषि के साथ ही जुड़ता है। कृषि व डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अमेरिका के लिए खोलने की जिद बेमानी होगी

स्वदेशी केवल तत्कालीन नहीं बल्कि भारत की आत्मा का उद्घोष है। यह भारत की एकता, देशभक्ति एवं सामूहिक आकांक्षाओं का शंखनाद है। भारत में स्वदेशी का मंत्र समय-समय पर अलग-अलग रूपों में प्रकट हुआ है। यही मंत्र ब्रिटिश गुलामी के समय विदेशी सत्ता को उखाड़ने में भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर, वंदे मातरम के रूप में आया। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कराए गए परमाणु विस्फोट के बाद भी भारत में प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसका जवाब स्वदेशी के नारे ने दिया था। पूरी दुनिया को स्वदेशी भाव से समुचित प्रत्युत्तर दिया गया था। स्वदेशी के मंत्र से आवश्यक संयम एवं स्वावलंबन का भाव जगेगा और अनावश्यक रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भरता को मोह से हम बचेंगे। स्वदेशी के मंत्र पर अमल से डिफेंस उद्योग का विकास होगा, कृषि पैदावार बढ़ेगी, श्रम प्रधान उद्योग का विस्तार होगा। सार्वजनिक सेवाओं और मूलभूत उद्योगों का विस्तार होने से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर स्वदेशी के व्यवहार का आह्वान किया है। हम इसे अपने जीव नें अपनाकर भारत को पुनः अजेय ताकत के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यही समय की मांग है। ■

{लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) हैं}

केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के पुनौरा धाम में माता सीता की जन्मस्थली के समग्र विकास के लिए भूमि पूजन किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 08 अगस्त, 2025 को बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमिपूजन किया। श्री अमित शाह ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ भी किया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज मां जानकी के जन्मस्थान पुनौरा धाम मंदिर परिसर के समग्र विकास की नींव डालना न सिर्फ सीतामढ़ी, मिथिलांचल और बिहार बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत शुभ अवसर है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनौरा धाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का करोड़ों रुपए से विकास करने का काम किया है। यह न सिर्फ मिथिलांचल और बिहार बल्कि पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद का विषय है।

पुनौरा धाम में एक भव्य मंदिर का निर्माण

श्री अमित शाह ने कहा कि पुनौरा धाम में शक्तिस्वरूपा जगतजननी मां जानकी का भव्य मंदिर 68 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगभग 890 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। उन्होंने कहा कि इसमें से 137 करोड़ रुपये माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार और 728 करोड़ रुपये परिक्रमा पथ और बाकी रचनाओं पर खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि यहां पर परिक्रमा पथ, ध्यान केन्द्रवाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनर्निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताई जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 डी अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्री राम के साथ-साथ माता जानकी के जीवन के सभी प्रसंगों को भी बहुत अच्छे तरीक़े से देख सकेंगे।

वाल्मीकि नगर का विकास

श्री अमित शाह ने कहा कि इस परियोजना में 52 करोड़ रुपये की लागत से रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर का विकास कार्य, 31 करोड़ रुपये की लागत से मधुबनी में फुलहर का विकास, 24 करोड़ रुपये की लागत से सीतामढ़ी में पंथ पाकड़ का विकास, 23 करोड़ रुपये की लागत से अहिल्या स्थल, 13 करोड़ रुपये की लागत से राम रेखा घाट और 7 करोड़ रुपये की लागत से मुंगेर गया में सीता कुंड का विकास शामिल है।

श्री अमित शाह ने कहा कि श्री राम से माता सीता की पहली बार भेंट होने से लेकर लवकुश के जन्मस्थान, माता सीता के अंतिम निवास और पंथ पाकर तक सभी स्थानों को पुनर्जीवित कर मां सीता की जीवनकथा को देश की मातृशक्ति को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य है।

श्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए गुंडागर्दी, माफियाओं को संरक्षण, अपहरण और फिरौती के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पिछले 6 दौरों में बिहार के विकास के लिए 83 हज़ार करोड़ रुपये दिए हैं। ■

यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है: नरेन्द्र मोदी

हर किले से इतिहास का एक-एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जुलाई को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 124वीं कड़ी की शुरुआत करते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में खेल हो, विज्ञान हो या संस्कृति; बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े, हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया।

श्री मोदी ने कहा कि हम सभी को गर्व से भर देने वाली एक और खबर आई है यूनेस्को से। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है— 11 किले महाराष्ट्र में, एक किला तमिलनाडु में।

उन्होंने कहा कि हर किले से इतिहास का एक-एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। सल्हेर का किला, जहां मुगलों की हार हुई। शिवनेरी, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। किला ऐसा जिसे दुश्मन भेद न सके। खानदेरी का किला, समुद्र के बीच बना अद्भुत किला। दुश्मन उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। प्रतापगढ़ का किला, जहां अफजल खान पर जीत हुई, उस गाथा की गूंज आज भी किले की दीवारों में समाई है। विजयदुर्ग जिसमें गुप्त सुरंगें थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता का प्रमाण इस किले में मिलता है। मैंने कुछ साल पहले रायगढ़ का दौरा किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नमन किया था। ये अनुभव जीवन भर मेरे साथ रहेगा।

श्री मोदी ने कहा कि देश के और हिस्सों में भी ऐसे ही अद्भुत किले हैं, जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी भी झुकने नहीं दिया। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, जैसलमेर का किला तो विश्व प्रसिद्ध है। कर्नाटक में गुलबर्गा का किला भी बहुत बड़ा है। चित्रदुर्ग के किले की विशालता भी आपको कौतूहल से भर देगी कि उस जमाने में ये किला बना कैसे होगा!

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बांदा में है, कालिंजर किला। महमूद गजनवी ने कई बार इस किले पर हमला किया और हर बार असफल रहा। बुन्देलखंड में ऐसे कई किले हैं— ग्वालियर, झांसी, दतिया, अजयगढ़, गढ़कुंडार, चंदेरी। ये किले सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची-ऊंची दीवारों से झांकते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें, गौरव महसूस करें।

अनगिनत बलिदानों के बाद हमें मिली आज़ादी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आप कल्पना कीजिए, बिल्कुल भोर का वक्त, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर, तारीख है 11 अगस्त, 1908; हर गली, हर चौराहा, हर हलचल उस समय जैसे थमी हुई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में ज्वाला थी। लोगों ने जेल को घेर रखा था, जहां एक 18 साल का युवक अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश-प्रेम व्यक्त करने की कीमत चुका रहा था। जेल के अंदर, अंग्रेज अफसर,एक युवा को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। उस युवा के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि गर्व से भरा हुआ था। वो गर्व, जो देश के लिए मर-मिटने वालों को होता है। वो वीर, वो साहसी युवा थे, खुदीराम बोस। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने वो साहस दिखाया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। तब अखबारों ने भी लिखा था— "खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे की ओर बढ़े, तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी।" ऐसे ही अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद हमें आज़ादी मिली थी। देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था।

श्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना इसलिए तो क्रांति का महीना है। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो आंदोलन' की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस; हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं, लेकिन हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है, इसलिए हम 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाते हैं।

उन्होंने कहा कि 7 अगस्त, 1905 को एक और क्रांति की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुना लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात'

'मन की बात' केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनसंवाद और राष्ट्र निर्माण का प्रेरणास्रोत बन चुका है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 27 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी मंडल में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के 124वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बैजयंत जय पांडा, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े, नई दिल्ली से लोकसभा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज, भाजपा राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी डॉ. संजय मयूख और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रदीप भंडारी सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनसंवाद और राष्ट्र निर्माण का प्रेरणास्रोत बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे 'आत्मनिर्भर भारत' के मंत्र देश के लोगों के साथ किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जहां शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा का उल्लेख कर युवाओं में विज्ञान में जगी रुचि के बारे में बात की, वहीं यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की घोषणा को देश को समक्ष रखते हुए भारत की वीरता और संस्कृति पर गर्व व्यक्त किया। साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी वस्त्रों से जुड़ी प्रेरक कहानियों और झारखंड के गुमला के मछुआरों की जीवनगाथा से 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाया।

श्री नड्डा ने कहा कि 'स्वच्छ भारत मिशन' के 11 वर्षों की यात्रा और उसमें महिलाओं, युवाओं, समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी ने सिद्ध किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत आज जन-आंदोलनों बनकर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। श्री नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे 'मन की बात' में व्यक्त किए गए विचारों को जन-जन तक पहुंचाएं, स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता को बढ़ाएं और 'विकसित भारत बनाने के संकल्प में सहभागी बनें। ■

हथकरघा को एक नई ऊर्जा दी थी। इसी स्मृति में देश हर साल 7 अगस्त को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' मनाता है। इस साल 7 अगस्त को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी की लड़ाई के समय जैसे हमारी खादी ने आजादी के आंदोलन को नई ताकत दी थी, वैसे ही आज जब देश 'विकसित भारत' बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है।

आज भारत में 3,000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्ट-अप सक्रिय

श्री मोदी ने कहा कि टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक सेक्टर नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। आज टेक्सटाइल और परिधान बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस विकास की सबसे सुंदर बात यह है कि गांवों की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और स्टार्ट-अप शुरू करने वाले हमारे युवा सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत में 3,000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्ट-अप सक्रिय हैं। कई स्टार्ट्स-अप ने भारत की हैंडलूम पहचान को वैश्विक ऊंचाई दी है।

उन्होंने कहा कि 2047 के 'विकसित भारत' का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और 'आत्मनिर्भर भारत' का सबसे बड़ा आधार है— 'वोकल फॉर लोकल'। जो चीजें भारत में बनी हों, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदें और वही बेचें। ये हमारा संकल्प होना चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को कभी-कभी कोई काम नामुमकिन सा लगता है। लगता है, क्या ये भी हो पाएगा? लेकिन जब देश एक सोच पर एक साथ आ जाए, तो असंभव भी संभव हो जाता है। 'स्वच्छ भारत मिशन' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जल्द ही इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे। लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में 'स्वच्छ भारत मिशन' एक जन-आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जन-भागीदारी है।

उन्होंने कहा कि हर साल होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण ने इस भावना को और बढ़ाया है। इस साल देश के 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे इससे जुड़े। 15 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। ये कोई सामान्य संख्या नहीं है। ये 'स्वच्छ भारत' की आवाज है। ■

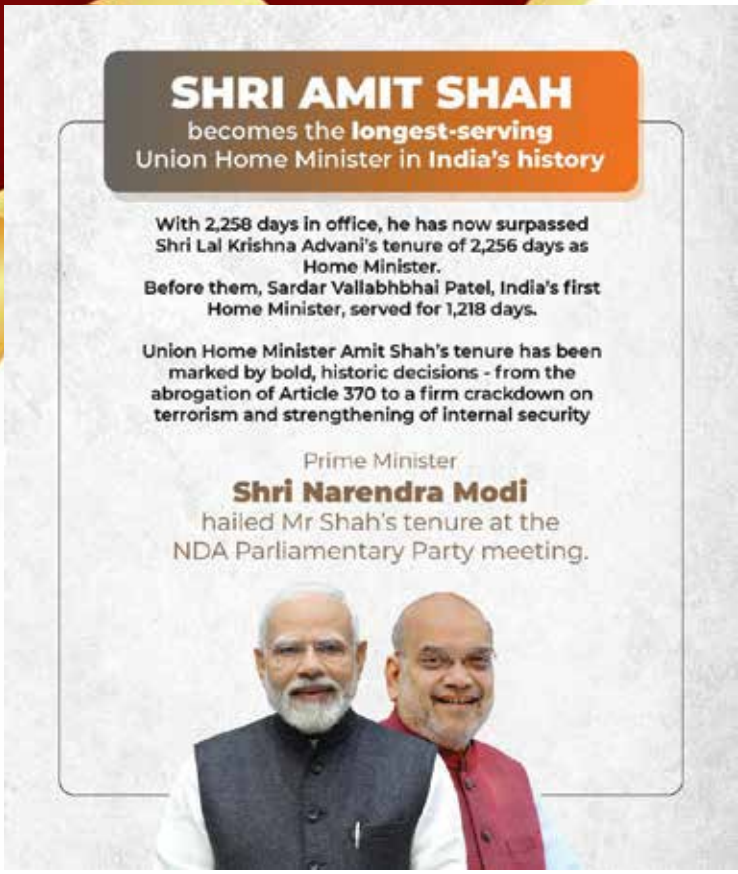

अमित शाह जी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बने

श्री अमित शाह जी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री रहने पर बधाई। अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक उन्मूलन से लेकर आतंकवाद के विरुद्ध कठोर रुख तक, उनका कार्यकाल अटूट संकल्प एवं निर्णायक नेतृत्व से चिह्नित रहा है। राष्ट्र आपके 'विकसित भारत' निर्माण के संकल्प की निरंतर सफलता की कामना करता है।

'परीक्षा पे चर्चा 2025' को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से किया गया सम्मानित

'परीक्षा पे चर्चा' को 'एक महीने में किसी नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण' के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह मान्यता 'मायगव' प्लेटफॉर्म पर आयोजित इस कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान प्राप्त 3.53 करोड़ वैध पंजीकरणों की अभूतपूर्व उपलब्धि का उत्सव मनाती है।

'परीक्षा पे चर्चा' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित एवं संचालित एक ऐसा अनूठा वैश्विक मंच है, जहां वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करते हैं। यह पहल परीक्षा के मौसम को सकारात्मकता, तैयारी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के उत्सव में बदल देती है, जिससे परीक्षाएं तनाव के बजाय प्रोत्साहन का एक अवसर बन जाती हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चार अगस्त को जारी विज्ञप्ति के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाणपत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री जितिन प्रसाद के साथ-साथ कई प्रमुख हितधारक उपस्थित थे। ■

इस अनूठी पहल की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदीजी का हार्दिक आभार: जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 4 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की #परीक्षापेचर्चा 2025 को एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

यह अनूठा मंच छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को परीक्षा के तनाव एवं सीखने के बारे में खुलकर बात करने का एक मंच प्रदान करता है। इसने परीक्षाओं को देखने और उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण को सचमुच बदल दिया है।

इस अनूठी एवं बहुप्रतीक्षित पहल को शुरू करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो पूरे देश के युवाओं को सामर्थ्य प्रदान करती है।

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 02 अगस्त, 2025 को विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

नई दिल्ली में 06 अगस्त, 2025 को कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करते एवं श्रमिकों के साथ चर्चा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हैदराबाद हाउस (नई दिल्ली) में 05 अगस्त, 2025 को फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति श्री फर्डिनेंड रोमुअलडेज मार्कोस जूनियर से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

आईसीएआर पूसा (नई दिल्ली) में 07 अगस्त, 2025 को एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 18 अगस्त, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

World Economic Outlook Growth Projections

(Real GDP, annual percent change)	2024	PROJECTIONS 2025	2026
World Output	3.3	3.0	3.1
Advanced Economies	1.8	1.5	1.6
United States	2.8	1.9	2.0
Euro Area	0.9	1.0	1.2
Germany	-0.2	0.1	0.9
France	1.1	0.6	1.0
Italy	0.7	0.5	0.8
Spain	3.2	2.5	1.8
Japan	0.2	0.7	0.5
United Kingdom	1.1	1.2	1.4
Canada	1.6	1.6	1.9
Other Advanced Economies	2.2	1.6	2.1
Emerging Market and Developing Economies	4.3	4.1	4.0
Emerging and Developing Asia	5.3	5.1	4.7
China	5.0	4.8	4.2
India	6.5	6.4	6.4
Emerging and Developing Europe	3.5	1.8	2.2
Russia	4.3	0.9	1.0
Latin America and the Caribbean	2.4	2.2	2.4
Brazil	3.4	2.3	2.1
Mexico	1.4	0.2	1.4
Middle East and Central Asia	2.4	3.4	3.5
Saudi Arabia	2.0	3.6	3.9
Sub-Saharan Africa	4.0	4.0	4.3
Nigeria	3.4	3.4	3.2
South Africa	0.5	1.0	1.3
Memorandum			
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.3	4.0	3.9
Low-Income Developing Countries	4.0	4.4	5.0

Source: IMF, *World Economic Outlook Update*, July 2025

Note: For India, data and forecasts are presented on a fiscal year basis, with FY 2024/25 (starting in April 2024) shown in the 2024 column. India's growth projections are 6.7 percent in 2025 and 6.4 percent in 2026 based on calendar year.

आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत किया

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व एवं साहसिक सुधारों के कारण भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, न केवल इस वर्ष, बल्कि 2026 में भी!

और जो लोग यह कहते रहते हैं कि 'भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है', उनके लिए यह आंकड़े वास्तविकता में एक कड़ा तमाचा हैं।

छायाकार: अजय कुमार सिंह